



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102023-249095
CG-DL-E-04102023-249095

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]
No. 237]

नई दिल्ली, बुधवार सितम्बर 27, 2023/ आश्विन 5, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ ASVINA 5, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

मामला सं. एमटीआर-07/2022

विषय: चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका आधारित पर्ल औद्योगिक पिगमेंट" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 7/17/2022-डीजीटीआर: - यह समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) को सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक या घरेलू उद्योग भी कहा गया है) की ओर से एक एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका बेस्ड पर्ल औद्योगिक पिगमेंट (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है ताकि चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित, फुज़ियान कुनकाई

मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध लगाये गये पाटनरोधी शुल्क के पुनर्मूल्यांकन और उसके बढ़ाने की जरूरत की जांच की जा सके।

2. चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां सं निर्यातित 'कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका आधारित पर्ल औद्योगिक पिगमेंट' के संबंध में एक पाटनरोधी जांच 9 मई, 2020 को शुरू की गई थी ताकि पाटन की प्रकृति और मात्रा तथा घरेलू उद्योग पर उसके क्षतिकारी प्रभाव की जांच की जा सके। प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम सं. 6/8/2020-डीजीटीआर, दिनांक 8 जून, 2021 के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी जिसे सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 47/2019 – सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 26 अगस्त, 2021 के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया था।
3. वर्तमान मध्यावधि समीक्षा नियमावली के नियम 23(1क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार शुरू की गई थी। प्राधिकारी के लिए किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से की गई विधिवत रूप से साक्षांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या परिस्थितियों में बदलाव के कारण मौजूदा पाटनरोधी शुल्क में संशोधन की आवश्यकता है।
4. प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य सहित विधिवत रूप से साक्षांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/17/2022-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितंबर, 2022 के माध्यम से एक मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत की थी। समीक्षा के दायरे को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु पर पहले से बढ़ाये गये पाटनरोधी शुल्क के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता की जांच के लिए बढ़ाया गया था।

ख. प्रक्रिया

5. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- क. प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/17/2022-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितंबर, 2022 के द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क से संबंधित एक मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की थी।
- ख. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में चीन के दूतावास संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशनों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध जांच की शुरुआत से उन्हें सूचित करने के लिए भेजी थी।
- ग. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और दूतावास के जरिये चीन की सरकार तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने ने लिखित में अनुरोध किया था, को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति प्रदान की थी।
- घ. प्राधिकारी ने संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरुआत करते हुए सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना में यथा विहित समय-सीमा (बढ़ाई की समय-सीमा सहित) में विहित ढंग और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर देने और लिखित में अपने विचार को अवगत कराने अवसर प्रदान किया।
- ङ. प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को अधिसूचना तथा याचिका के अगोपनीय अंश की प्रतियां भेजीं।
- च. चीन की सरकार से भारत में उसके दूतावास के जरिये उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों से विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गये पत्र पर प्रश्नावली की एक प्रति नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार चीन से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के ब्यौरों के साथ चीन के दूतावास को भी भेजी गई थी।
- छ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है:
 - i. फुज़ियान कुनकाई मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड

- ii. झेजियांग कोलोरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
- iii. हेनान लिंगबाओ न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं से आवश्यक सूचना मंगाने के लिए अधिसूचना और प्रश्नावलियों की एक-एक प्रति भेजी थी।
 - i. एशियन पेंट्स लिमिटेड
 - ii. आर.सी. इंटरनेशनल
 - iii. एफएक्स पिगमेंट्स प्रा. लिमिटेड
 - iv. काजल केमिकल्स
 - v. केपीएल इंटरनेशनल लिमिटेड
 - vi. जियोक्रोम इंटरनेशनल
 - vii. पॉलीकेम एक्सपोर्ट्स
 - viii. कुनकाई इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- झ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित संबंधित आयातक ने आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।
 - i. कुनकाई इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- ञ. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 (12 माह) की है।
- ट. जांच अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए सौदावार आयात आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) और डीजी सिस्टम्स से प्राप्त किये गये थे। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है और डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर तुलना तथा निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों के मिलान के लिए भरोसा किया है।
- ठ. आवेदक और प्रतिवादी निर्यातकों/आयातकों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी।
- ड. सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों/उत्तरों/टिप्पणियों के अगोपीनय अंश को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल करने का अनुरोध किया गया था।
- ढ. क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी भी कहा गया है) को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखते हुए भारत में संबद्ध वस्तु की ईष्टमत लागत और तर्कसंगत लाभ के आधार पर निर्धारित किया गया है। ऐसी क्षतिरहित कीमत इसलिए ज्ञात की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ण. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए 21 दिसंबर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की थी। मौखिक सुनवाई में अपने विचार रखने वाले हितबद्ध पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों और उसके बाद खंडन अनुरोधों, यदि कोई हों, के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। पक्षकारों ने अपने अगोपीनय अनुरोध अन्य हितबद्ध पक्षकारों से साझा किये और अपने खंडन प्रस्तुत करने की उन्हें सलाह दी गई।

- त. जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्कों और सूचना पर उनके साक्ष्यों द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत समझे जाने वाले सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- थ. प्राधिकारी ने जांच के दौरान स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उस सूचना की सत्यता से स्वयं को संभव सीमा तक संतुष्ट किया है, जो इस अंतिम जांच परिणाम का आधार है तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का संगत और संभव समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है।
- द. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की प्रयाप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी गोपनीयता दावे को जहां आवश्यक हो, स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।
- ध. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह अंतिम जांच परिणाम दर्ज किये हैं।
- न. इस जांच के अनिवार्य तथ्यों जो अंतिम जांच परिणाम के आधार हैं, वाला एक प्रकटन विवरण 18 सितंबर, 2023 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए 23 सितंबर, तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन विवरण के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर उनके इस अंतिम जांच परिणाम से संगत पाये जाने की सीमा तक विचार किया गया है।
- प. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- फ. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 75. 34रूपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार था:

"7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका आधारित पर्ल औद्योगिक पिगमेंट" है।

8. विचाराधीन उत्पाद रासायनिक रूप से टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटेड माइका नैनियस और चमत्कार पर्लेसेंट सिगमेंट है और इसे बाजार में वाणिज्यिक रूप से टाइटेनियम डाइऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड कोटेड माइका पर्ल पिगमेंट या पर्ल लस्टर पिगमेंट या पर्ल पिगमेंट के रूप में जाना जाता है। इसे व्यापक रूप से कतिपय अकार्बनिक पिगमेंट/कलर करने और यथा वर्णित अन्य प्रभावों के लिए प्रयोग किया जाता है जो चमकदार/साइनिंग फ्रॉस्टेड प्रभावों देते हैं जैसे पर्लेसेंट प्रभाव, कोटिंग के लिए मैटलिंग प्रभाव, इंक और प्लास्टिक अनुप्रयोग।"

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

7. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- i. आवेदन 'नेचुरल माइका आधारित पर्ल पिगमेंट' को संबद्ध उत्पाद बताता है। यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी स्पष्ट करें कि आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना में कॉस्मेटिक ग्रेड शामिल नहीं हैं।
- ii. पीयूसी के दायरे को कॉस्मेटिक ग्रेड शामिल करने के लिए एमटीआर जांच में बढ़ाया नहीं जा सकता है। नियम 23 (1क), जांच शुरुआत सूचना और आवेदक के लिखित अनुरोध का संदर्भ दिया गया है।
- iii. संबद्ध आयातों का स्रोत बताये बिना यह मान्यता की औद्योगिक ग्रेड, कास्मेटिक ग्रेड के रूप में आयातित है, एक अनुमान प्रतीत होता है।

- iv. घरेलू उद्योग द्वारा लगाया गया आरोप केवल मान्यता है, क्योंकि आयात कीमतों में केवल 9 प्रतिशत की कमी आई है, जो कच्ची सामग्री की अस्थिरता के कारण हो सकती है।
- v. घरेलू उद्योग को ऐसी स्थिति को कवर करने के लिए प्रवंचनारोधी जांच का आवेदन दायर करना चाहिए था, जहां किसी वस्तु को भिन्न वर्णन के साथ आयातित किया जा रहा है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

8. संबद्ध वस्तु कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका आधारित पर्ल औद्योगिक पिगमेंट है। औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए कॉस्मेटिक ग्रेड के काफी अधिक आयात हो रहे हैं। यह अनुरोध है कि प्राधिकारी स्पष्ट करें कि कॉस्मेटिक अनुप्रयोग के लिए कॉस्मेटिक ग्रेड लागू शुल्क से छूट प्राप्त है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार वर्णित था:

"7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका आधारित पर्ल औद्योगिक पिगमेंट" है।

8. विचाराधीन उत्पाद रासायनिक रूप से टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटेड माइका नैनियस और चमत्कार पर्लेसेंट सिगमेंट है और इसे बाजार में वाणिज्यिक रूप से टाइटेनियम डाइऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड कोटेड माइका पर्ल पिगमेंट या पर्ल लस्टर पिगमेंट या पर्ल पिगमेंट के रूप में जाना जाता है। इसे व्यापक रूप से कतिपय अकार्बनिक पिगमेंट/कलर करने और यथा वर्णित अन्य प्रभावों के लिए प्रयोग किया जाता है जो चमकदार/साइनिंग फ्रॉस्टेड प्रभावों देते हैं जैसे पर्लेसेंट प्रभाव, कोटिंग के लिए मैटलिंग प्रभाव, इंक और प्लास्टिक अनुप्रयोग।"

10. उत्पाद का दायरा वही है जैसा मूल जांच में था। मूल जांच में विचार की गई निम्नलिखित पीसीएन पद्धति को संबद्ध जांच के प्रयोजनार्थ अपनाया गया है।

क्र. सं.	गैर-ऑटोमोबाइल	पार्टिकल आकार
1.	चाँदी- 1	छोटा (डी50<17)- एस नियमित (डी50 17-30 के बीच)- आर बड़ा (डी50>30)- एल विशेष- एक्स
2.	सोना- 2	छोटा (डी50<17)- एस नियमित (डी50 17-30 के बीच)- आर बड़ा (डी50>30)- एल विशेष- एक्स
3.	आइरीडिसेंट- 3	छोटा (डी50<17)- एस नियमित (डी50 17-30 के बीच)- आर बड़ा (डी50>30)- एल विशेष- एक्स
4.	अर्थ टोन्स (कांस्य/तांबा/मैरून)- 4	छोटा (डी50<17)- एस नियमित (डी50 17-30 के बीच)- आर बड़ा (डी50>30)- एल विशेष- एक्स
5.	अन्य- 5	छोटा (डी50<17)- एस नियमित (डी50 17-30 के बीच)- आर बड़ा (डी50>30)- एल विशेष- एक्स
	ऑटोमोबाइल अनुप्रयोग	
1.	चाँदी- 1	छोटा (डी50<17)- एस नियमित (डी50 17-30 के बीच)- आर

		बड़ा (डी50>30)- एल विशेष- एक्स
2.	सोना- 2	छोटा (डी50<17)- एस नियमित (डी50 17-30 के बीच)- आर बड़ा (डी50>30)- एल विशेष- एक्स
3.	आइरीडिसेंट- 3	छोटा (डी50<17)- एस नियमित (डी50 17-30 के बीच)- आर बड़ा (डी50>30)- एल विशेष- एक्स
4.	अर्थ टोन्स) कांस्य/तांबा/मैरून)- 4	छोटा (डी50<17)- एस नियमित (डी50 17-30 के बीच)- आर बड़ा (डी50>30)- L विशेष- एक्स
5.	अन्य- 5	छोटा (डी50<17)- एस नियमित (डी50 17-30 के बीच)- आर बड़ा (डी50>30)- L विशेष- एक्स

11. संबद्ध वस्तु को टैरिफ कोड 3206 11 को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 32 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
12. यह भी नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद संबद्ध वस्तु को 6 अंकीय स्तर पर समर्पित कोड के अलावा विभिन्न एचएसएन कोडों अर्थात् 32064990, 32061900, 32041759, 32041739, 32041720, 32041790 और 32071040 के अंतर्गत भी आयातित किया जा रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
13. वर्तमान जांच एक मध्यावधि समीक्षा है जो पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन की मात्रा के पुनः निर्धारण और शुल्क में बदलाव की जरूरत की जांच के दायरे तक सीमित है। समीक्षा के दायरे में उत्पाद के दायरे की पुनः जांच शामिल नहीं है। अतः वर्तमान समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही होगा जो पूर्ववर्ती जांच में था।
14. प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के दायरे के बार में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध नोट करते हैं। कॉस्मेटि ग्रेड को मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा गया था और उसे वर्तमान जांच से भी बाहर रखा गया है। कुछ इच्छुक पार्टियों ने बहिष्करण के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। यह स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक अभ्रक आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट है। आगे यह नोट किया गया है कि यह स्पष्टीकरण उत्पाद के दायरे में संशोधन के समान नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। इस बात पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी कोई विवाद नहीं उठाया है। इसके मद्देनजर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुतः संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।
16. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह मुद्दा उठाया है कि घरेलू उद्योग को ऐसी स्थिति जहां परिवर्तित वर्णन के साथ किसी वस्तु का आयात हो रहा है, को कवर करने के लिए प्रवंचनारोधी आवेदन दायर करना चाहिए। प्राधिकारी नोट

करते हैं कि यह प्रवंचनारोधी मामला नहीं है, क्योंकि परिवर्तित वर्णन के साथ वस्तु आयातित नहीं हो रही है, बल्कि कतिपय पीसीएन के अंतर्गत आयातों में वृद्धि हुई है और अन्य में कमी आई है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

17. एडी नियमावली के नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

“(ख) ‘‘घरेलू उद्योग’’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ‘‘घरेलू उद्योग’’ शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।’’

18. यह आवेदन सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में विचाराधीन उत्पाद का एक मात्र उत्पादक है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक के पास कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। आवेदक न तो चीन के संबद्ध उत्पादक या निर्यातक से और न ही भारत में संबद्ध वस्तु के आयातक से संबंधित हैं। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

19. आवेदक या अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ड. समीक्षा का दायरा

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- i. नियम 23 (1क) का दायरा सीमित है और प्राधिकारी को सीमित समीक्षा करने की शक्ति नहीं देता है। प्राधिकारी द्वारा हाल में कोई सीमित समीक्षा नहीं की गई है। व्यापार जांचों के लिए प्रचालन प्रथाओं संबंधी मैनुअल पर भरोसा किया गया है और 28 मार्च, 2019 जूट उत्पादों के आयातों में बंद करने संबंधी पत्र जारी किया गया है।
- ii. नियम 23 (1क) प्राधिकारी को केवल मौजूदा शुल्क वापस लेने और न कि किसी परिस्थिति में उसे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है। इंडियन ग्रेफाइट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम वित्त मंत्रालय एवं अन्य (13 अप्रैल, 2006) पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह निर्णय एसएसआर जांच तक सीमित है।
- iii. नियम 23 (1क) प्राधिकारी को आवेदक द्वारा अनुरोध के अनुसार समीक्षा की शुरुआत को कुनकाई तक सीमित करने के लिए बाध्य नहीं करता है। प्राधिकारी समीक्षा के दायरे को परिभाषित करने के लिए इस उपबंध के अंतर्गत अधिकार संपन्न हैं। इस बात पर विचार करते हुए कि आवेदक ने सभी उत्पादकों/निर्यातकों के विरुद्ध जांच शुरुआत पर कोई आपत्ति नहीं की है, वर्तमान में प्राधिकारी के समक्ष इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- iv. आवेदक द्वारा कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18 जून, 2019 पर भरोसा निराधार है, क्योंकि इसे नियम 23 के संदर्भ में जारी किया गया था न कि नियम 23 (1क) के संदर्भ में। बाद वाले में क्षति जांच स्पष्ट रूप से आवश्यक है। ओएम को इस मुद्दे के संदर्भ में पढ़ा जाए और वह नियमावली को अतिव्याप्त नहीं कर

सकता है। प्राधिकारी की प्रक्रिया सीमित समीक्षा के अनुरोध के आधार पर जांच शुरू करने की नहीं रही है।

- v. चीन जन. गण. से एल्युमिनियम अलॉय रोड व्हील्स संबंधी 30 अगस्त, 2022 की मध्यावधि जांच पर भरोसा करना गलत है, क्योंकि उस मामले के तथ्य वर्तमान मामले से अलग हैं।
- vi ऋषिरूप पॉलीमर्स पर भरोसा करना गलत है क्योंकि निर्णय का अनुपात केवल शुल्क समाप्त करने से संबंधित है जिससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अन्य मापदंडों की जांच करना अपेक्षित नहीं है।
- vii. अन्य उत्पादकों के लिए पाटन या क्षति मार्जिन के पुनर्निर्धारण से बचने की मांग करने का आवेदक का वास्तविक कारण यह है कि उन्हें गुणवत्ता संबंधी समस्याएं आ रही हैं, उनकी सीमित उत्पादन क्षमता है, जो उनके लिए अपने बाजार हिस्से के बनाये रखने के लिए उत्पाद के आयात को आवश्यक बना देती है।
- viii. कोलोरे और लिंगबाओ इस बात पर विवाद नहीं करते कि नियम 23 (1क) प्राधिकारी को सीमित समीक्षा करने की अनुमति देता है। नियम 23 (1क) प्राधिकारी को चीन जन. गण. से सभी उत्पादकों के विरुद्ध समीक्षा शुरू करने की अनुमति देता है। यूनाइटेड स्टेट्स - वियतनाम से कतिपय थ्रिम्प पर पाटनरोधी उपाय (डब्ल्यूटी/डीएस/429/आर) में डब्ल्यूटीओ की पैनल रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

21. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- i. पीओआई में परिवर्तित परिस्थितियों में फुज़ियान कुनकाई मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड से निर्यातित कास्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका आधारित पर्ल औद्योगिक पिगमेंट पर लागू मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के पुनर्निर्धारण और उसे बढ़ाने की जरूरत की समीक्षा को आवश्यक बनाती हैं।
- ii. कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18 जून, 2019 के साथ पठित नियम 23 (1क) पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की सीमित समीक्षा की अनुमति देता है। ऋषिरूप पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अपर सचिव¹ तथा चीन जन. गण. से एल्युमिनियम अलॉय रोड व्हील्स के आयातों संबंधित एमटीआर जांच (दिनांक 30 अगस्त, 2022) पर भी भरोसा किया गया है।
- iii. सभी अन्य निर्यातकों की समीक्षा से गैर-भागीदार चीन के उत्पादकों के प्रति पक्षपात होगा और डीजीटीआर पर अधिक बोझ पड़ेगा। इन निर्यातकों के संबंध में परिस्थितियों में परिवर्तन दर्शाने वाला कोई प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य रिकार्ड में नहीं है।
- iv. व्यापार जांच के लिए प्रचालन प्रथाओं के मैनुअल का उल्लेख मैनुअल के पृष्ठ xi में यथा उल्लिखित विरोधाभासों/अंतरों के मामले में नहीं किया जा सकता है। यह प्राधिकारी को विभिन्न जांचों और अंतिम निर्णयों में मामला विशिष्ट अंतरों को मान्यता देने की अनुमति देता है और अंतिम निर्णय तथ्यों के आधार पर लिया जाएगा।
- v. इस तर्क के संबंध में, कि नियम 23 (1क) प्राधिकारी को केवल शुल्क वापस लेने की शक्ति देता है, थाई ऐंक्रेलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2010(253) ईएलटी 564 (ट्राई-डेल.) में सेस्टेट के निर्णय पर भरोसा किया गया है। यह माना गया था कि वह प्रयोजन जिसके लिए कानून लेवी का अधिकार देता है; यह पाटन के विरुद्ध उसे पूर्णतः कारगर बनाने के लिए उसे बढ़ाने या घटाने की अनुवर्ती और आनुसंगिक शक्ति भी देता है।

¹ (2006 (196) E.L.T. 385 (SC)),

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

22. वर्तमान जांच नियम 23 (1क) के अनुसार शुरू की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रावधान हैं:
- “(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी जहां आवश्यक हो, वहां स्वयं की पहल पर या ऐसे किसी हितबद्ध पक्षकार जो ऐसी समीक्षा की जरूरत को सही सिद्ध करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, किसी पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के बाद तर्कसंगत समय बीत गया हो तथा ऐसी समीक्षा के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी उसे वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करेंगे, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि उक्त पाटनरोधी शुल्क को हटाया गया या उसमें बदलाव किया गया तो घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए अब शुल्क की आवश्यकता नहीं है।”*
23. प्राधिकारी ने समीक्षा के लिए प्रावधान करते हुए दिनांक 18 जून, 2019 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रावधान हैं:
- “6. घरेलू उद्योग सहित कोई हितबद्ध पक्षकार मौजूदा एडी/सीवीडी शुल्क की राशि या रूप में में बदलाव के लिए एडी और सीवीडी नियमावली के नियम क्रमशः 23 और 24 के अंतर्गत समीक्षा की मांग कर सकता है। उन परिवर्तित परिस्थितियां जिनकी वजह से समीक्षा आवश्यक हो सकती है, में कच्ची सामग्री की कीमतें, लागत, शुल्क संरचना, विनिमय दर आदि में परिवर्तन शामिल है। प्राधिकारी ऐसी किसी समीक्षा के लिए नई पीओआई पर विचार करेंगे और इस चुनी गई पीओआई के लिए सभी प्रमुख मापदंडों जैसे पाटन मार्जिन या सब्सिडी मार्जिन, क्षति मार्जिन और पहुंच मूल्य का मूल्यांकन करेंगे। अपने रूप सहित संशोधित एडी/सीवीडी इस व्यापक पुनः परिकलन पर आधारित होगा।”*
24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान समीक्षा आवेदक द्वारा कथित परिस्थिति में परिवर्तन के आधार पर शुरू की गई है। वर्तमान जांच इस जांच तक सीमित है कि क्या परिस्थितियों ऐसा कोई परिवर्तन हुआ है जो पाटनरोधी शुल्क की राशि में परिवर्तन को उचित ठहराता है। अपने आवेदन में आवेदक ने निम्नलिखित आरोप लगाये हैं:
- क. भारतीय बाजार में निर्यातकों द्वारा निर्यातित उत्पाद प्रोफाइल में भारी बदलाव हुआ है।
 - ख. कच्ची सामग्री के कारण लागत में वृद्धि निर्यात कीमत में वृद्धि द्वारा आनुपातिक रूप से प्रदर्शित नहीं होती है।
 - ग. कुछ पीसीएन की निर्यात कीमत में वृद्धि कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि से कम है।
 - घ. कुछ पीसीएन के लिए निर्यात कीमत में भारित औसत वृद्धि ऋणात्मक है जबकि लागत में भारित औसत वृद्धि घनात्मक है।
25. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि नियम 23 (1क) का दायरा सीमित है और प्राधिकारी को सीमित समीक्षा करने या शुल्क बढ़ाने की शक्ति नहीं देता है। यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी द्वारा मध्यावधि समीक्षा के दौरान शुल्क की राशि को घटाकर या बढ़ाकर या वही रखकर शुल्क दरों में परिवर्तन करने की संगत परिपाटी रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने पूर्व में भी नियम 23 के अंतर्गत शुल्क के पुनर्निर्धारण के लिए समीक्षाएं की हैं। एक्रिलोनिट्राइल बूटाडीन रबड़) एनबीआर) के आयातों से संबंधित ऐसी एक समीक्षा को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और उसे शीर्ष न्यायालय द्वारा नियम 23 के प्रावधानों से संगत पाया गया था।
26. चीन जन. गण. से एल्यूमिनियम अलॉय रोड व्हील्स के आयातों से संबंधित दिनांक 30 अगस्त, 2022 की हाल की एमटीआर जांच में भी प्राधिकारी ने पाटन/क्षति मार्जिन की पुनः जांच के लिए सीमित समीक्षा की है। अतः वर्तमान समीक्षा को नियम 23 के प्रावधानों से इतर नहीं माना जा सकता है।

27. इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 18 जून, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से यह बताते हुये एक दिशानिर्देश जारी किया किया घरेलू उद्योग सहित कोई हितबद्ध पक्षकार शुल्क की राशि या रूप बदलने के लिए नियम 23 के अंतर्गत समीक्षा की शुरुआत की मांग कर सकता है।
28. इसके अलावा, नियम 23 (1) में उल्लेख है कि “अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान के अंतर्गत लागू कोई पाटनरोधी शुल्क तब तक और उस आवश्यक सीमा तक लागू रहेगा जब तक वह क्षति करने वाले पाटन का विरोधी हो”। “उस सीमा तक” शब्द का अर्थ शुल्क की अवधि या मात्रा है। इसके अलावा, नियम 23 (1) में “यदि उक्त पाटनरोधी शुल्क हटाया या उसमें बदलाव किया जाता है और इसलिए अब आवश्यक नहीं है”, के लिए प्रावधान हैं। इस प्रकार यह नियम प्राधिकारी को शुल्क की मात्रा (राशि) में बदलाव करने की अनुमति देता है।
29. पूर्वोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि वर्तमान समीक्षा का दायरा केवल पूर्व जांच में शुल्क के अधीन सभी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन के पुनः निर्धारण की आवश्यकता की जांच तक सीमित है। ऐसी समीक्षा का दायरा दिनांक 18 जून, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित नियम 23 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।
30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने मेसर्स फुज़ियान कुनकाई मैटेरियल टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड (कुनकाई) तक सीमित समीक्षा की मांग की थी। प्राधिकारी यूएस – थ्रिम्प II (वियतनाम) [डब्ल्यूटी/डीएस429/आर] में डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं जिसमें यह माना गया है कि प्राधिकारी के पास क्रमवार या कंपनी विशिष्ट आधार पर कोई समीक्षा करने का विवेकाधिकार निहित है। ऐसा निर्णय हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये विशिष्ट अनुरोध और समीक्षा करने की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए पक्षकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दोनों पर निर्भर करता है।
31. वर्तमान मामले में, चीन से केवल एक निर्यातक पर लागू शुल्क की सीमित समीक्षा के लिए आवेदक का अनुरोध प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर मानने योग्य नहीं था, क्योंकि आवेदक द्वारा दावा की गई परिवर्तित परिस्थितियों ने चीन से अन्य निर्यातकों की निर्यात कीमत और उत्पादन लागत को भी प्रभावित किया होगा। आवेदक ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था कि क्यों/कैसे परिवर्तित परिस्थितियां केवल कुनकाई पर लागू होती हैं और चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के अन्य निर्यातकों पर लागू नहीं होतीं। इसके आलोक में प्राधिकारी ने इस बात से संतुष्ट होने के बाद सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए शुल्क की वर्तमान समीक्षा की है कि आवेदक द्वारा कथित कच्ची सामग्री की लागत और निर्यात कीमत सहित परिस्थिति में बदलाव की संबद्ध देश में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए जांच की जानी अपेक्षित है।
32. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई इस दलील के संबंध में कि कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि हुई है परंतु निर्यात कीमत में कोई आनुपातिक वृद्धि नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार यह देखा गया है कि कतिपय पीसीएन में कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि मूल जांच की अवधि की तुलना में समीक्षा की अवधि के दौरान निर्यात कीमत से अधिक रही है। आगे विश्लेषण से यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री की औसत लागत में वृद्धि मूल जांच की अवधि की तुलना में समीक्षा अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के औसत पहुंच मूल्य में वृद्धि से अधिक रही है।
33. नीचे तालिका भी यही प्रवृत्ति दर्शाती है:

विवरण	2020-2021 (रू./केजी)	2021-2022 (पीओआई) (रू./केजी)	वृद्धि/कमी (%)
प्रमुख कच्ची सामग्री की लागत	***	***	***
सूचीबद्ध	100	124	20-30
पहुंच मूल्य	***	***	***

सूचीबद्ध 1	100	112	10-20
------------	-----	-----	-------

आंकड़ों के विश्लेषण के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि प्रमुख कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि से क्षति मापदंड प्रभावित हुये हैं जो घरेलू उद्योग के हित के लिए हानिकारक हैं। अतः पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की समीक्षा करना आवश्यक है।

च. गोपनीयता

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

34. आवेदक ने आयात आंकड़ों के स्रोत के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। कुवैत, सऊदी अरब और यूएसए से मोनो एथिलीन ग्लाइकोल (27 अक्टूबर 2022) और विट्रीफाइड टाइल में सेस्टेट के आदेश पर भरोसा किया गया है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

35. पीसीएन और निर्यात आंकड़ों संबंधी विश्लेषण को प्रकट नहीं करना। व्यापार सूचना 01/2022 के साथ पठित सीमा शुल्क की धारा 135कक द्वारा लागू निषेध के कारण है। घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावे व्यापार सूचना 01/2013 के अनुपालन में हैं।

च.3. प्राधिकारी जांच

36. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

37. प्राधिकारी मानते हैं कि कोई सूचना जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है या जिसे जांच के पक्षकारों द्वारा उचित कारण बताते हुए गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है उसे प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना जाएगा और सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

38. आवेदन में प्रस्तुत आयात आंकड़ों के संबंध में बाजार आसूचना स्रोतों से प्राप्त आयात आंकड़े शेयर नहीं किये जा सकते क्योंकि ऐसे आंकड़ों का प्रकाशन सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की 135कक के अंतर्गत “तक समय प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत जब ऐसा करना अपेक्षित न हो” निषिद्ध है। व्यापार सूचना के साथ पठित नियम 5(2) के प्रावधानों के अनुसार आवेदन में प्रदत्त आंकड़े इस संबंध में आवेदन प्रपत्र विनिर्दिष्ट करते हुए जारी किये गये हैं। अतः आयात आंकड़ों संबंधी आवेदक का गोपनीयता का दावा प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है।

39. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी गोपनीयता के दावे को जहां आवश्यक हो, स्वीकार किया है और ऐसी

सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश देते हुए कि वे एक दूसरे को ई-मेल के माध्यम से अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश शेयर करें। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया था।

40. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने गोपनीयता का उचित कारण नहीं बताया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने याचिका के अगोपनीय अंश में एक औचित्य तालिका प्रस्तुत की है। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये गोपनीयता के दावों को उनसे संतुष्ट होने के बाद स्वीकार किया है।

छ. विविध

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

41. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- संबद्ध वस्तु के निर्यात के ब्यौरे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं और उनका परिचालन सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135कक का उल्लंघन है। आवेदक ने प्रस्तुत आंकड़ों का स्रोत और प्रमाणिकता नहीं बताई है। आवेदक ने या तो मनगढ़ंत जानकारी प्रस्तुत की है या उसे अवैध रूप से प्राप्त किया है।
- शुल्क बढ़ाना जनहित के विरुद्ध होगा, क्योंकि आवेदक निर्यातानुमुखी है, मांग – आपूर्ति में भारी अंतर है और इसे एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

42. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- संबद्ध वस्तु के निर्यात ब्यौरे बाजार आसूचना से लिये गये हैं। उनकी सटीकता और सत्यता के बारे में प्रतिवादी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार हैं।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

43. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत निर्यात डेटा पर तर्कों के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किया गया डेटा नामित प्राधिकारी के निष्कर्षों को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि प्राधिकरण डीजीसीआईएंडएस और डीजी सिस्टम डेटा पर निर्भर था।

ज. सामान्य मूल्य, पाटन मार्जिन

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

44. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- कुनकाई द्वारा संबद्ध वस्तु की प्रति इकाई औसत कच्ची सामग्री लागत में गिरावट आई है और मूल जांच की पीओआई की तुलना में पीओआई के दौरान निर्यात कीमत में वृद्धि हुई है।

- ii. घरेलू उद्योग कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि की मात्रा को साक्ष्य के साथ सिद्ध करने में विफल रहा है। कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि सभी उत्पादकों पर लागू है और इसलिए समीक्षा कुनकाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
- iii. झेजियांग कोलोरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को अलग शुल्क प्रदान नहीं करना चाहिए। टीडीआई समीक्षा जांच और जूट समीक्षा जांच पर भरोसा किया गया है।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

45. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- i. मूल जांच की पीओआई और वर्तमान पीओआई के दौरान बेचे गये उत्पाद बिक्री मिश्रण में परिवर्तन हुआ है। मूल जांच में पीसीएन वार विश्लेषण किया गया था जो दर्शाता है कि जांच की वर्तमान अवधि के बिक्री मिश्रण में परिवर्तन पाटन और क्षति मार्जिन प्रभावित हुआ है जिससे कुनकाई की समीक्षा आवश्यक है।
- ii. निर्यात कीमत में आनुपातिक वृद्धि कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के बावजूद कतिपय पीसीएन की निर्यात कीमत में कटौती हुई है।
- iii. प्राधिकारी मूल जांच में किये गये अनुसार विधिवत रूप से समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करते हैं।
- iv. कुनकाई की प्रति इकाई कच्ची सामग्री लागत में गिरावट के संबंध में यह अनुरोध किया गया है कि वर्तमान जांच में इसकी कोई प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि कुनकाई (चीन) एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है जैसा मूल जांच में निर्धारित है।
- v. कच्ची सामग्री की लागत में परिवर्तन के कारण परिस्थिति में बदलाव सभी निर्यातकों के लिए नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।
- vi. पाटनरोधी शुल्क अन्य कंपनियों के लिए परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए कोई बदली हुई परिस्थितियां सिद्ध नहीं की गई है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में यथा उल्लिखित मान्यताओं का खंडन करने के लिए कोई पूरक प्रश्नावली तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी को संबंधित नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करनी होगी:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार

अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार या पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इन उत्पादकों/निर्यातकों की सामान्य मूल्य की गणना इस प्रकार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-1 का पैरा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तथापि, जब ऐसा आधार संभव न हो केवल तभी प्राधिकारी सामान्य मूल्य को भारत में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर निर्धारित कर सकते हैं।
48. वर्तमान मामले में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत संबंधी कोई दावा या सूचना प्रदान नहीं की है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. के लिए कोई वैकल्पिक प्रतिनिधि देश प्रस्तावित नहीं किया है। इसके आलोक में प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि पैरा 7 के पहले परंतुक के आवेदन में विचार करने के लिए कोई पर्याप्त सूचना या प्राधिकारी के पास इसके लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
49. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अन्य देशों को पीयूसी निर्यातों के ट्रेड मैप आंकड़ों में प्राधिकारी द्वारा विहित पीसीएन संबंधी ब्यौरे नहीं हैं। इसके अलावा, पीयूसी का कोई समर्पित एचएसएन कोड नहीं है। अतः अन्य देशों को पीयूसी के निर्यात संबंधी पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी पैरा 7 के विकल्प 2 को नहीं अपना सकते हैं।
50. अतः प्राधिकारी ने अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आवश्यक समायोजनों तथा बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा लाभ के तर्कसंगत योग के साथ विचार किया है।

ज.4. निर्यात कीमत का निर्धारण

51. चीन जन. गण. से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है:

- क. फुज़ियान कुनकाई मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड
- ख. झेजियांग कोलोरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
- ग. हेनान लिंगबाओ न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड

- क. फुज़ियान कुनकाई मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड

निर्यात कीमत

52. फुज़ियान कुनकाई मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड ने भारत में असंबंधित और संबंधित दोनों उपभोक्ताओं को *** यूएस डॉलर के बीजक मूल्य पर *** एमटी संबद्ध वस्तु का सीधे निर्यात किया है। संबंधित आयातक ने जांच में सहयोग किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित सौदे निकट स्थित हों। संबंधित आयातक के उत्तर से यह देखा गया है कि आयातक द्वारा की गई बिक्रियां लाभ दर्शाती हैं। तदनुसार, समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय आदि के लिए समायोजन की अनुमति देने के बाद भारित औसत कारखानाद्वारा निर्यात कीमत और भारित औसत पहुंच मूल्य क्रमशः *** यूएस डॉलर/ एमटी और *** यूएस डॉलर/ एमटी बनता है।

- ख. झेजियांग कोलोरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

निर्यात कीमत

53. जांच अवधि के दौरान झेजियांग कोलोरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को *** यूएस डॉलर बीजक मूल्य पर *** एमटी विचाराधीन उत्पाद का सीधे निर्यात किया है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय परिवहन, बीमा, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय आदि के लिए समायोजन की अनुमति देने के बाद भारत औसत कारखानाद्वारा निर्यात कीमत और भारत औसत पहुंच मूल्य क्रमशः *** यूएस डॉलर/ एमटी और *** यूएस डॉलर/ एमटी बनता है।

ग. हेनान लिंगबाओ न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड

निर्यात कीमत

54. जांच अवधि के दौरान हेनान लिंगबाओ न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को *** यूएस डॉलर बीजक मूल्य पर *** एमटी विचाराधीन उत्पाद का सीधे निर्यात किया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय आदि के लिए समायोजन की अनुमति देने के बाद भारत औसत कारखानाद्वारा निर्यात कीमत और भारत औसत पहुंच मूल्य क्रमशः *** यूएस डॉलर/ एमटी और *** यूएस डॉलर/ एमटी बनता है।

घ. चीन से जांच के अधीन अन्य असहयोगी निर्यातक

55. ऐसे असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों जिन्होंने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है, के लिए निर्यात कीमत पर सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदत्त और भारत में आयातकों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों विचार करते हुए नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध आयात कीमत के आधार पर विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

पाटन मार्जिन

56. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन नीचे तालिका से देखा जा सकता है। यह देखा जाएगा कि पाटन मार्जिन में परिवर्तन हुआ है।

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/एमटी)	निवल निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
फुज़ियान कुनकाई मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
झेजियांग कोलोरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	70-80
हेनान लिंगबाओ न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड	***	***	***	***	70-80
असहयोगी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	90-100

झ. क्षति

झ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

57. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- i. आवेदक व्यापार उपचार जांच के लिए प्रचालन प्रथाओं के मैनुअल द्वारा यथा आवश्यक "परिवर्तित परिस्थितियों की स्थायी प्रकृति" की पूर्व शर्त को पूरा करने में विफल रहा है। कार्बन ब्लैक (दिनांक 28 फरवरी, 2013) तथा टीडीआई में क्लोजर पत्र पर भरोसा किया गया है।
- ii. आवेदक को संबद्ध आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है क्योंकि स्थापित क्षमता में 17 प्रतिशत की वृद्धि, क्षमता उपयोग में 22 प्रतिशत की वृद्धि, उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि, घरेलू बिक्री में 25 प्रतिशत की वृद्धि, निर्यात बिक्री में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि, घरेलू बिक्री कीमत में वृद्धि, प्रति दिन उत्पादकता में 40 तक वृद्धि हुई है।
- iii. कोई कारणात्मक संबंध नहीं हैं, क्योंकि क्षमता में वृद्धि हुई है, ब्याज लागत, मूल्यहास बढ़ा है और निर्यात बिक्री में गिरावट आई है।
- iv. ब्याज लागत में वृद्धि और मूल्य हास को देखते हुए प्राधिकारी को स्टार्ट-अप लागत, असाधारण लागत, अनावर्ती लागत और अत्यधिक मूल्यहास के रूप में लागत का समायोजन करना चाहिए।

झ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

58. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- i. पाटनरोधी करार, एडी नियमावली और आवेदन प्रपत्र के अनुसार परिवर्तित परिस्थितियों की स्थायी प्रवृत्ति दर्शाने की जरूरत नहीं है।
- ii. प्राधिकारी की प्रक्रिया पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में स्थायी प्रकृति की जांच की रही है। चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "4, 4डायमिनो स्टिलबेने 2, डाइसल्फोनिक एसिड" (डीएसडीए) के आयातों संबंधी मध्यावधि समीक्षा (दिनांक 26 सितंबर, 2016) पर भरोसा किया गया है।
- iii. आवेदक द्वारा कथित परिवर्तित परिस्थिति एक वर्ष को दर्शाती है और उसमें पहले निर्धारित पाटन और क्षति मार्जिन प्रभावित हुआ है। इस प्रकार ये बातें यह दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं कि परिवर्तन स्थायी प्रकृति का है।
- iv. क्षति संबंधी तर्कों के बारे में यह अनुरोध किया गया है कि वर्तमान जांच पहले से निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन तथा मूल जांच में लगाये गये शुल्क की राशि के पुनः निर्धारण तक सीमित है।

झ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

59. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को क्षति की जांच करनी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच संबद्ध देश से सभी निर्यातकों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की राशि निर्धारित करने के लिए शुरू की गई थी। चीन से केवल एक निर्यातक पर लागू शुल्क की सीमित समीक्षा के लिए आवेदक ने अनुरोध किया है।
60. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के कारण हो रही क्षति के बारे में कोई दावा नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि वर्तमान जांच सीमित मध्यावधि समीक्षा है जिसे संबद्ध देश से संबद्ध निर्यातकों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के पुनः निर्धारण के लिए शुरू किया गया था। इसलिए प्राधिकारी ने मूल जांच में निर्यातकों पर लागू पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की पुनः गणना की है। तथापि, प्राधिकारी ने अधिक व्यापक जांच के लिए क्षति संबंधी मापदंडों की जांच की है।

61. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दलील दी है कि परिवर्तित परिस्थिति की स्थायी प्रकृति सिद्ध नहीं की गई है। प्राधिकारी ने चीन जन. गण. अथवा वहां से निर्यातित "4, 4डायमिनो स्टिलबेने2, 2डाइसल्फोनिक एसिड" (डीएसडीएस) दिनांक 26 सितंबर, 2016 में निम्नलिखित को पहले नोट किया है।

“निर्णायक समीक्षा और मध्यावधि समीक्षा से संबंधित नियमावली की भाषा को जानबूझकर अलग रखा गया है ताकि शुल्क वापसी की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए अधिक सावधानी पर जोर दिया जा सके। एडी नियमावली के नियम 23(1क) में संभावना “नहीं” शब्द पर जोर देना पाटनरोधी शुल्क की समय से पहले समामि की जांच के समय उच्चतर और कड़े दायित्व को दर्शाता है।”

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा कड़ा दायित्व केवल तभी उत्पन्न होता है जब पाटनरोधी शुल्क को समय से हटाने की जांच की जाए। इसके अलावा, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच को आवेदक द्वारा प्रदत्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य से संतुष्ट होने के बाद शुरू किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने एक वर्ष की अवधि के लिए सूचना देकर परिवर्तित परिस्थिति को सिद्ध किया है।
63. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान क्षति संबंधी सूचना की जांच की है। इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक द्वारा कथित परिवर्तित परिस्थिति एक वर्ष को दर्शाती है और उसने पहले निर्धारित पाटन और क्षति मार्जिन को प्रभावित किया है, प्राधिकारी मानते हैं कि इससे पर्याप्त रूप से पता चलता है कि परिवर्तन स्थायी प्रकृति का है। प्राधिकारी इस तथ्य को नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पूरी क्षति अवधि में जारी रही है, जो यह भी दर्शाता है कि परिवर्तित परिस्थितियां स्थायी प्रकृति की हैं।
64. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि क्षति के सभी मापदंडों में खराबी प्रदर्शित हो। कुछ मापदंड खराबी दर्शा सकते हैं जबकि अन्य नहीं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर वस्तुनिष्ठ रूप से विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की जांच की है। इसके अलावा, चूंकि विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है। इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध आयातों पर मौजूदा शुल्क के प्रभाव पर घरेलू उद्योग को क्षति की जांच करते समय विचार करना अपेक्षित है। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या मौजूदा उपाय क्षति पहुंचाने वाले पाटन की भरपाई के लिए पर्याप्त हैं।

झ.4. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग आकलन/स्पष्ट खपत का आकलन

65. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में संबद्ध वस्तु की मांग या स्पष्ट खपत को भारत में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	91	125
3	चीन जन. गण. से आयात	एमटी	1,841	2,003	2,471	1,871
4	अन्य देशों से आयात	एमटी	231	178	192	294
5	कुल मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	115	112

66. यह देखा गया है कि पीयूसी की मांग में क्षति अवधि के पहले तीन वर्षों में वृद्धि हुई है जबकि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में मामूली गिरावट आई है। समग्र रूप से क्षति अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देश से आयात मात्रा

67. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या संबद्ध देश से पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है, इसका विश्लेषण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1)	चीन जन. गण.	एमटी	1,841	2,003	2,471	1,871
2)	अन्य देश	एमटी	231	178	192	294
3)	कुल आयात	एमटी	2,072	2,181	2,663	2,166
4)	संबद्ध देश के संबंध में					
i.	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	165	85
ii.	मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	117	91
iii.	कुल आयात	%	89	92	93	86

67. यह देखा गया है कि:

- क) संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में 2020-21 तक वृद्धि हुई है, परंतु अगस्त, 2021 में पाटनरोधी शुल्क लगने के कारण पीओआई में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की बिक्री में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान में वृद्धि हुई है।
- ख) पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद चीन जन. गण. के आयातों के पास भारतीय मांग और भारत को कुल आयातों का प्रमुख हिस्सा है।

झ.5. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

69. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या कथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में काफी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करना है ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण यदि कोई हो, के जरिये की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क) कीमत कटौती

70. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कटौती प्रभाव निम्नानुसार ज्ञात होते हैं:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1)	निवल बिक्री प्राप्ति	रू./प्रति	***	***	***	***
2)	पहुंच मूल्य	रू./प्रति	3,80,425	3,79,897	3,94,105	4,43,452
3)	कीमत कटौती	रू./प्रति	***	***	***	***
4)	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
5)	कीमत कटौती	रेंज %	25-35	20-30	10-20	0-10

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद कीमत कटौती काफी अधिक और सकारात्मक है।

ख) कीमत हास/न्यूनीकरण

72. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में हास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में भारी कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमत में परिवर्तन की निम्नानुसार जांच की गई है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1)	विक्रियों की लागत	रू./प्रति	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	101	105	108
2)	बिक्री कीमत	रू./प्रति	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	93	91	94
3)	पहुंच कीमत	रू./प्रति	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	100	104	117

73. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रहना जारी है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद वर्ष 2020-21 और जांच अवधि में लागत के स्तर पर भी अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में असमर्थ है। संबद्ध देश से पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का हास कर रहे हैं।

झ.6. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

74. नियमावली के अनुबंध-11 में यह प्रावधान घरेलू उद्योग को पाटित के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति में प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों की जांच शामिल होगी। घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति संबंधी विभिन्न मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों पर दिये गये विभिन्न तथ्यों और तर्कों पर वस्तुनिष्ठ रूप से विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की जांच की है।

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां

75. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां नीचे तालिका में दी गई हैं।

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	117
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	81	119
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	81	102
बिक्रियां (घरेलू)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	91	125

76. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता में पीओआई के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों में पीओआई के दौरान वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण हुई है।

ख) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

77. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे तालिका में दर्शाये गये हैं।

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	रू./एमटी	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति		100	6	-58	-54
लाभ/हानि	रू. लाख	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति		100	6	-53	-68
नकद लाभ प्रति यूनिट	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	48	14	9
नकद लाभ	रू. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	45	12	11
पीबीआईटी प्रति यूनिट	रू./एमटी	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति		100	12	-35	-34
पीबीआईटी	रू. लाख	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति		100	11	-32	-43
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति		100	13	-49	-48

78. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद पीओआई के दौरान घाटा हो रहा है।
- ख. घरेलू उद्योग अपने नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओआई में 2018-19 और 2019-20 में प्राप्त स्तरों तक वृद्धि करने में असमर्थ है। घरेलू उद्योग के निवेश पर रिटर्न 2020-21 और जांच अवधि के दौरान 1% से कम है। घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भारतीय बाजार में अनुचित कीमत पर आयातों के प्रवेशों के कारण अपने निष्पादन में सुधार करने में असमर्थ है। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क से समाधान नहीं हो रहा है।

ग) मालसूची

79. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है।

स्टॉक (मात्रा)	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्	100	142	127	132

80. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा रखी गई औसत सूची में पीओआई के दौरान वृद्धि हुई है।

घ) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

81. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	91	99	108
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	100	75	125
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	100	85	108
मजदूरी	रू. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	116	92	119

82. यह देखा गया है कि पिछले वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या, उत्पादकता और भुगतान की गई मजदूरी में वृद्धि हुई है।

ड.) पाटन की मात्रा

83. पाटन की मात्रा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले पाटित आयातों की मात्रा का संकेतक हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि संबद्ध देश के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

च) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

84. घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा है और वह सकारात्मक अंशदान अर्जित करने में असमर्थ है। पाटित आयातों के कारण उद्योग के प्रचालन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

झ.7 क्षति मार्जिन की मात्रा

85. प्राधिकारी प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षतिरहित कीमत पर क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना के लिए विचार किया गया है। गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए, कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग, उपयोगिताओं और घरेलू उद्योग द्वारा क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता और उपयोग पर विचार किया गया है ताकि कच्चे माल की दक्षता से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त किया जा सके। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय प्रभावित न किया जाए। नियमावली के अनुबंध III में यथा विहित क्षतिरहित कीमत ज्ञात करने के लिए व्याज, लाभ और करों के लिए कर पूर्व आय के रूप में अनुमति प्राप्त विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक तर्कसंगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की अनुमति दी गई है।

86. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है।

87. ऊपर यथा निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और उसे नीचे तालिका में दिया गया है।

क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक/निर्यातक	एनआईपी (यूएस डॉलर/एमटी)	पहुंच मूल्य (यूएस डॉलर/एमटी)	क्षति मार्जिन (यूएस डॉलर/एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
फुज़ियान कुनकाई मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
झेजियांग कोलोरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
हेनान लिंगबाओ न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
असहयोगी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	60-70

ज. गैर-आरोपण विश्लेषण

88. प्राधिकारी के लिए पाटित आयातों से इतर किसी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जिससे उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो ताकि उन अन्य कारकों से होने वाली क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गये आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेश तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों से इतर उक्त कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

89. अन्य देशों से आयात या तो अधिक कीमत पर हैं या नगण्य स्तर पर हैं।

ख. मांग में संकुचन

90. यह देखा गया है कि नोट किया गया है कि मांग में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

ग. खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

91. खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

92. कोई ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

93. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में किसी बदलाव को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

च. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू बाजार की दृष्टि से घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है।

छ. घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों का निष्पादन

95. प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है।

ज. घरेलू उद्योग की उत्पादकता

96. घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादकता से संबंधित आंकड़े प्रदान किये हैं।

ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

97. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- i. कोलोरे के पीसीएन-वार पहुंच मूल्य के परिकलन में कुछ विसंगतियां हैं जिससे कुछ पीसीएन के लिए पहुंच कीमत गलती से आपसे में बदल दी गई प्रतीत होती है।
- ii. प्राधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि घरेलू उद्योग का कौन से पीसीएन कोलोरे के साथ तुलना के लिए चुने गए थे। प्राधिकारी को इसे स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि अन्यथा यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
- iii. न तो याचिकाकर्ता ने चोट के संबंध में कोई प्रस्तुतिकरण दिया है और न ही शुरूआती अधिसूचना याचिकाकर्ता को लगी चोट पर वर्तमान समीक्षा के दायरे को कवर करती है। प्राधिकरण को चोट की जांच नहीं करनी चाहिए।
- iv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए सबसे पहले अवसर दिए जाने के बिना तथाकथित क्षति के संबंध में याचिकाकर्ता के आंकड़ों और आरोपों का विश्लेषण किया जाना प्राधिकारी के लिए प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में है।
- v. संबद्ध आयातों की मात्रा जांच की अवधि के दौरान काफी घटी है और क्षति की अवधि में भी नगण्य है। याचिकाकर्ता ने संबद्ध आयातों का प्रतिकूल प्रभाव दर्शाने के लिए अपनी बिक्री कीमत जानबूझकर कम की है।
- vi. याचिकाकर्ता की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री मात्रा क्षति की अवधि की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बढ़ी है। जो वित्तीय हानियां हुई हैं वे अचल परिसंपत्तियों और मूल्य ह्रास लागतों में वृद्धि के कारण हैं।
- vii. पाटित आयातों और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है, घरेलू उद्योग को विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद क्षति की अवधि के दौरान हानियां हो रही हैं।
- viii. पाटन की मात्रा में वर्तमान समीक्षा में काफी गिरावट आई है क्योंकि मूल जांच में प्राधिकारी ने अन्य सभी उत्पादकों का पाटन मार्जिन 200- 300प्रतिशत की रेंज में निर्धारित किया था जबकि वर्तमान एमटीआर में मार्जिन 90- 100प्रतिशत है।
- ix. नियम 1 23(क) प्राधिकारी को यह अधिकार नहीं देता कि वे सीमित मध्यावधि समीक्षा करें। प्राधिकारी द्वारा वह उस समय किया गया था जब जूट उत्पादों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की मध्यावधि समीक्षा शुरू करने के लिए अनुरोध की समाप्ति हो रही थी।
- x. आवेदक द्वारा दावा किए गए निर्यातों में उत्पाद स्वरूप में परिवर्तन भ्रामक, बनाया गया और गलत सूचना पर आधारित अथवा गैर-कानूनी साधनों के माध्यम से उत्पादित है क्योंकि यह विस्तृत/सूचना (क) सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है (ख) लेनदेनवार आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है (ग) आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में नहीं दी गई थी और (घ) उत्तरदाता निर्यातक द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तर में भी उपलब्ध है।
- xi. आवेदक को निर्यात ब्यौरे का स्रोत प्रकट करना चाहिए और यदि वह गैर-कानूनी माध्यमों से उत्पादित अथवा बनाई गई पाई जाए तो उस जांच को रद्द किया जाना चाहिए।
- xii. नियम 23 (1क) प्राधिकारी को अधिकार देता है कि वे शुल्कों को वापस लें (आंशिक अथवा पूरे) और किसी भी परिस्थिति में उसे न बढ़ाएं।
- xiii. वर्तमान जांच बिना किसी न्याय अधिकार के है क्योंकि नियमावली के जांच की शुरूआत की अधिसूचना और न ही आवेदन पत्र में यह सूचना दी गई है कि परिवर्तित परिस्थितियां समाप्त होने वाली प्रकृति की है। आवेदन पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के प्रावधानों के पूर्णतः उल्लंघन में है।
- xiv. कच्ची सामग्री और उत्तरदाता निर्यातक की निर्यातक कीमत में वृद्धि के संबंध में आवेदक किए गए दावे गलत, भ्रामक, निर्मित और गलत हैं क्योंकि (क) उत्तरदाता/निर्यातक के संबद्ध सामानों की प्रति यूनिट औसत कच्ची सामग्री लागत में मूल जांच की बाद की अवधि की तुलना में जांच की अवधि के दौरान

3. 64 प्रतिशत तक गिरावट आई है और (ख) उत्तरदाता निर्यातक की औसत निर्यात कीमत में मूल जांच की जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि के दौरान काफी वृद्धि अर्थात् लगभग 7 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

- xv. केवल एक वर्ष की अवधि के लिए सूचना प्रदान करना यह सिद्ध नहीं करता कि परिवर्तित परिस्थितियां टिकाऊ प्रवृत्ति की हैं।
- xvi. शुल्क बढ़ाना जनहित के विरुद्ध होगा क्योंकि आवेदक की एकाधिकारिक स्थिति सृजित करने वाला उत्पादक है, अतः वे सशक्त रूप से निर्यातोन्मुख हैं और घरेलू मांग को पूरी करने में असमर्थ हैं जिससे मांग व आपूर्ति अंतराल बन रहा है।
- xvii. प्राधिकारी की यह सतत परिपाटी है कि वे उन पीसीएन के लिए घरेलू उद्योग के निकटतम पीसीएन पर विचार करें, जिनका जांच की अवधि के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यात किया गया था न कि जांच की अवधि के दौरान वाणिज्यिक मात्राओं में घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित किए गए थे और/अथवा बेचे गए थे।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

98. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- i. घरेलू उद्योग ने एक निर्यातक के विरुद्ध सीमित समीक्षा की मांग की। पर्याप्त आधारों के बिना और उन परिकल्पनाओं के आधार पर जो घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई परिस्थितियों के आधार पर हैं, जांच के क्षेत्र को व्यापक बनाने से अन्य निर्यातकों के प्रभावित होने की संभावना मात्र एक अवधारणा है।
- ii. क्षति मापदंडों की जांच मूल जांच में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा पुनः निर्धारित करने तक सीमित मामले में आवश्यक नहीं है।
- iii. पाटनरोधी शुल्क की समय पूर्व वापसी के लिए दायर किए गए मामले में टिकाऊ प्रकृति सिद्ध हैं। किसी भी निर्यातक ने इस साक्ष्य के साथ विवाद नहीं किया है कि परिवर्तित परिस्थितियां प्रकृति में टिकाऊ नहीं हैं।
- iv. सभी 9 एचएसएन कोड जिनके तहत विचाराधीन उत्पाद भारत में आयात किया जा रहा है, शुल्क तालिका के अंतर्गत शामिल किया जाना है।
- v. वर्तमान जांच में इसे हटाया जाना कॉस्मेटिक आवेदन के लिए कॉस्मेटिक ग्रेड का ही है। उसे स्पष्ट करना विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को व्यापक बनाना नहीं बनता।
- vi. कुछ कच्ची सामग्री की खपत की मात्रा क्षति की अवधि में अलग-अलग है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे एनआईपी निर्धारण के लिए उन्हें अनुकूल न बनाएं।
- vii. एनआईपी कानून में खपत अदक्षताओं को सामान्य किए जाने का प्रावधान है न कि खपत में अंतर। प्राधिकारी को यदि वे एनआईपी के संबंध में घरेलू उद्योग के दावों को रद्द करते हैं तो विस्तृत जांच परिणाम देने चाहिए।
- viii. चूंकि घरेलू उद्योग ने विदेशी उत्पादकों द्वारा दिए पीसीएन में समान पीसीएन नहीं दिए हैं अतः प्राधिकारी को तुलनीय पीसीएन के लिए एनआईपी निर्मित करना चाहिए और उत्पाद की भौतिक विशेषताओं में अंतरों के लिए समायोजन करने चाहिए। भारत के डब्ल्यू टी ओ प्रस्ताव पर विश्वास किया जाता है।
- ix. प्राधिकारी को उन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए शेष शुल्कों की सिफारिश करनी चाहिए जो वर्तमान जांच में सहयोगी हैं।
- x. घरेलू उद्योग पर यह साक्ष्य देने की जिम्मेदारी का कभी भी बोझ नहीं था कि परिवर्तित परिस्थिति इस जांच के किसी भी चरण में कुनकई पर भी लागू थी। यह उन निर्यातकों पर है जिन्होंने साक्ष्य देने के लिए जांच में सहयोग किया है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

99. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां पुनरावृत्ति प्रकृति की हैं जिनकी उपयुक्त रूप से पहले ही जांच कर दी गई है और अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराओं में जिनका पर्याप्त रूप से समाधान कर दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटनपश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की जांच निम्नलिखित रूप में की गई है।
100. संबद्ध देश के सभी निर्यातकों को शामिल करने के लिए समीक्षा को व्यापक किए जाने के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्धारित करने में प्राधिकारी का विशेषाधिकार है कि क्या वे ऑर्डर-वार अथवा कंपनी विशिष्ट आधार पर समीक्षा के क्षेत्र को बढ़ाएं। वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने यह संतुष्ट होने के बाद सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए शुल्क की वर्तमान समीक्षा की है कि आवेदक द्वारा लगाए गए आरोप में कच्ची सामग्री और निर्यात कीमत की लागत सहित परिस्थितियों में परिवर्तन की संबद्ध देश में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त उत्पादकों/निर्यातक द्वारा दायर उत्तरों से प्राधिकारी संतुष्ट हुए हैं कि संबद्ध सामानों की कीमतें उत्पादन लागत में परिवर्तन के अनुरूप नहीं रही हैं।
101. घरेलू उद्योग और उत्तरदाताओं दोनों ने तर्क दिया है कि सीमित दायरे वाली जांच के लिए क्षति परीक्षण आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है, प्राधिकरण नोट करता है कि भले ही वर्तमान जांच सीमित है, विषय पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क की पुनः मात्रा निर्धारित करने के लिए मध्यावधि समीक्षा शुरू की गई है। संबद्ध देश के निर्यातकों के मामले में, प्राधिकारी ने बदली हुई परिस्थितियों की स्थायी प्रकृति का पता लगाने के लिए क्षति मापदंडों की जांच की है।
102. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख करते हुए प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का उल्लेख किया है कि उन्हें कुछ समय तक घरेलू उद्योग के क्षति मानदंडों पर टिप्पणी करने के अवसर प्रदान नहीं किया गया था जब तक कि प्रकटन का चरण न हो। प्राधिकारी के विवेक पर घरेलू उद्योग ने अपने क्षति संबंधी प्रपत्र प्रस्तुत किए हैं और दिनांक 16 दिसंबर, 2022 को अपने आवेदन पत्र के परिशिष्ट के रूप में उसका अगोपनीय रूपांतर साझा किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसकी जांच करने और उस पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए पूरा समय दिया गया है। इसके अतिरिक्त, क्षति मानदंडों संबंधी टिप्पणियां संगत शीर्ष के अंतर्गत हल कर दी गई है।
103. शुल्क तालिका में एचएसएन कोड शामिल किए जाने संबंधी अनुरोध नोट कर दिए गए हैं और उन्हें शुल्क तालिका में शामिल कर दिया गया है।
104. नियम 23 (1क) के क्षेत्र के संबंध में किए गए सभी अनुरोध, टिकाऊ प्रकृति, परिवर्तित परिस्थिति जो जांच की शुरुआत में भी घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत निर्यात आंकड़ों की सत्यता और जनहित तथा उत्पाद क्षेत्र संबंधी स्पष्टीकरण संगत शीर्षों के अंतर्गत पहले ही हल कर दिए गए हैं।
105. तुलनीय पीसीएन के लिए एनआईपी निर्मित किए जाने के संबंध में और एनआईपी से संबंधित भौतिक विशेषताओं और अन्य अंतरों के लिए समायोजन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में सर्वप्रथम प्राधिकारी ने पीसीएन से पीसीएन का मिलान किया और जहां कहीं मिलान नहीं हुआ, वहां उन्होंने कुल पीसीएन के लिए निकटतम एनआईपी पर विचार किया जो डी जी टी आर की सतत परिपाटी के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किए जाते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि उत्पाद श्रेणी/स्वरूप समान हैं। यही पद्धति प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में अपनाई गई थी।
106. जहां तो कोलरेज की पीसीएन वार पहुंच मूल्य के परिकलनों में विसंगतियों का संबंध है, उन्हें वर्तमान जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए ठीक कर दिया गया है।
107. जहां तक घरेलू उद्योग के पीसीएन को कोलोरे के साथ तुलना के लिए चुने जाने पर प्रकटीकरण पर तर्क का संबंध है, प्राधिकरण ने लगातार अभ्यास किया है। जहां घरेलू उद्योग ने बिल्कुल समान पीसीएन की आपूर्ति की है, वर्तमान निर्धारण के लिए उसी पर विचार किया गया है। हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां आयात मात्रा में कुछ पीसीएन शामिल हैं जो जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किए गए हैं, इन पीसीएन के लिए गैर-हानिकारक मूल्य या सामान्य मूल्य की गणना उचित समायोजन के साथ निकटतम पीसीएन के आधार पर की गई है, यदि आवश्यक हुआ।

ठ. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

108. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- i. शुल्क में वृद्धि करना जनहित के विरुद्ध होगा क्योंकि आवेदक निर्यातोन्मुख हैं, अतः भारी मांग आपूर्ति अंतराल है और एकाधिकारिक स्थिति बनाता है।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

109. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- i. जनहित संबंधी तर्क के संबंध में प्राधिकारी द्वारा मूल जांच के किए गए विश्लेषण पर विश्वास का संदर्भ दिया जाता है जहां उन्होंने उपभोक्ताओं पर शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाया। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच में कोई उपभोक्ता/प्रयोक्ता प्रतिभागिता नहीं है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

110. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के प्रचालनों पर विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों को बढ़ाए जाने के संभावित प्रभावों सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, स्रोतों को बदलने की उपभोक्ताओं की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्कों का प्रभाव, उन कारकों जिनसे संशोधित पाटनरोधी शुल्कों के परिणामस्वरूप नई स्थिति में समायोजन के बढ़ने अथवा विलंब होने की संभावना है, के संबंध में सूचना मांगी। विचाराधीन उत्पाद के किसी भी प्रयोक्ता/आयातक ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है अथवा प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।

111. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्य रूप में घरेलू उद्योग को पाटन की अंतिम परिपाटियों से होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में एक खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी ने माना कि पाटनरोधी शुल्कों में संशोधन के संबद्ध सामानों के कीमत स्तरों तथा भारत में संबद्ध सामानों का प्रयोग करके विनिर्मित अन्य निचले स्तर के उत्पादों सहित कीमत स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है।

112. तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से कम नहीं होगी, घरेलू उद्योग की होने वाली गिरावट संबद्ध देश के कम कीमत के संबद्ध आयातों के कारण होने वाली घरेलू उद्योग की गिरावट रुकेगी और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्पों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

113. घरेलू उद्योग के एकाधिकारिक व्यवहारों के मुद्दे के संबंध में यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन पाटन को समाप्त करना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है तथा भारतीय बाजार में बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित करना है। पाटनरोधी शुल्कों से यह बात नहीं बनती कि कोई कंपनी, यहां तक कि एकाधिकारिक है, अनुचित आयातों के विरुद्ध प्राधिकारी की कार्रवाइयों के लिए अनुरोध करने से प्रतिबंधित नहीं है। वर्तमान मामले में यह तथ्य कि विचाराधीन उत्पाद का केवल एक भारतीय उत्पादक है और पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने से संबंधित उत्पाद का स्वदेशी उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा तथा यह तथ्य कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं पर बहुत कम है, जैसा कि मूल मामले के अंतिम जांच परिणामों में नोट किया गया, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित में होगा।

ड. निष्कर्ष

114. विचाराधीन उत्पाद, गोपनीयता, आवेदन पत्र की पर्याप्तता और परिशुद्धता, प्रश्नावली के उत्तरों, जांच के क्षेत्र, पाटन और क्षति मार्जिन के पुनः निर्धारण, घरेलू उद्योग को तथाकथित रूप से क्षति पहुंचाने वाले अन्य कारकों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों की जांच करने के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में उठाए गए मुद्दों पर समुचित रूप से कार्रवाई की है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

- i. वर्तमान जांच में विचार किया गया उत्पाद दायरा और पीसीएन पद्धति वही है जो मूल जांच में परिभाषित है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृतिक अभ्रक आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।
- ii. संबद्ध सामानों में 8अंकीय स्तर पर समर्पित कोड नहीं है और विभिन्न एचएसएन कोडों के तहत आयात किया जाता रहा है जो इस जांच परिणाम के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है।
- iii. नियमों के नियम 2(बी) के तहत आवेदक घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमों के नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।
- iv. वर्तमान जांच का क्षेत्र दिनांक 18 जून, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित नियम 23(1क) के प्रावधानों से शासित है और पूर्व जांचों में शुल्कों के अधीन आने वाले सभी निर्यातकों के लिए पाटन/क्षति मार्जिन के पुननिर्धारण तक सीमित है।
- v. सहयोगी निर्यातकों के पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक हैं।
- vi. प्राधिकारी ने अधिक व्यापक जांच के लिए क्षति मानदंडों की जांच की है, यहां तक कि यद्यपि, वर्तमान जांच मूल जांच में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के पुननिर्धारण तक सीमित है।
- vii. बदली हुई परिस्थिति की स्थायी प्रकृति को घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत स्थापित किया गया है।

ढ. सिफारिश

115. प्राधिकरण नोट करता है कि मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पार्टियों को सूचित किया गया था और घरेलू उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पार्टियों को डंपिंग, क्षति और कारण लिंक के पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।
116. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि मौजूदा कर्तव्यों में संशोधन की आवश्यकता वाली परिस्थिति बदल गई है, प्राधिकरण की राय है कि सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 47/2021 - सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 26 अगस्त 2021 के तहत चीन से आयात के संबंध में उपाय को संशोधित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, नीचे दी गई तालिका के कॉलम 7 में निर्दिष्ट राशि के अनुसार निश्चित एंटीडंपिंग शुल्क इस अधिसूचना की तारीख से शुल्क की शेष अवधि तक यानी 25.08.2026 तक लगाए जाने की सिफारिश की जाती है, जो सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 47/2021-सीमा शुल्क दिनांक 26.08.2021 केंद्र सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार करने की स्थिति में, चीन पीआर से उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के सभी आयात के तहत लगाया गया है।
117. इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार और सीमा प्रशुल्क नियम 1975 की धारा 3,8 ख,9 ,9 क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्कों के लागू स्तर पर निर्धारणीय मूल्य होगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	32064990, 32061900, 32041759, 32041739, 32041720, 32041790, 32071040	'कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका आधारित पर्ल औद्योगिक पिगमेंट	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	फुज़ियान कुनकाई मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड	299	प्रति मी.ट.	अम.डॉ.
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित	झेजियांग कोलोरे टेक्नोलॉजी	2913	प्रति मी.ट.	अम.डॉ.

				कोई भी देश	डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड			
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	हेनान लिंगबाओ न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड	2353	प्रति मी.ट.	अम.डॉ.
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	क्र.सं. 1 से 3 के अलावा कोई अन्य उत्पादक	3144	प्रति मी.ट.	अम.डॉ.
5	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन.गण.	कोई उत्पादक	3144	प्रति मी.ट.	अम.डॉ.

ण. आगे की प्रक्रिया

118. इस कार्यालय जापान से उत्पन्न होने वाली केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 27th September, 2023

(Case no. MTR-07/2022)

Subject:-Mid Term Review of anti-dumping duty imposed on the imports of "Natural mica-based pearl industrial pigments excluding cosmetic grade" originating in or exported from China

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 7/17/2022-DGTR:—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Rules”) thereof.

1. The Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) received an application, on behalf of Sudarshan Chemical Industries Limited (hereinafter also referred to as the “applicant” or the “domestic industry”) requesting initiation of a mid-term review investigation of anti-dumping duty imposed on imports of natural mica based pearl industrial pigments excluding cosmetic grade (hereinafter also referred to as the “subject goods” or the “product under consideration”) to examine the need to re-evaluate and enhance the anti-dumping duty levied

against imports of the subject goods exported by Fujian Kuncai Material Technology Company Limited, originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).

2. An anti-dumping investigation with respect to natural mica-based pearl industrial pigments excluding cosmetic grade originating in or exported from China PR, was initiated on 9th May 2020 to examine the nature and extent of dumping and its injurious effect on the domestic industry. The Authority vide its Final Findings No. 6/8/2020-DGTR, dated 8th June 2021 recommended imposition of definitive anti-dumping duties, which were given effect vide Customs Notification No. 47/2019 – Customs (ADD), dated 26th August 2021 for a period of five years.
3. The present mid-term review was initiated in accordance with Section 9A of the Act, read with Rule 23(1A) of the Rules. The Authority is required to review, based on a duly substantiated request made by or on behalf of any interested parties, as to whether the change in circumstances warrant modification of the existing anti-dumping duty.
4. In view of the duly substantiated application with *prima facie* evidence and in accordance with Section 9A of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated a mid-term review investigation vide Notification No. 7/17/2022-DGTR dated 30th September 2022. The scope of the review was enhanced to examine the need for redetermination of the anti-dumping duty earlier extended on the subject goods from the subject country.

B. PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed regarding the subject investigation:
 - a. The Authority vide Notification No. 7/17/2022-DGTR dated 30th September 2022, published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating a mid-term review investigation concerning anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods from the subject country.
 - b. The Authority sent a copy of the public notice to the Embassy of China in India, known producers and exporters from the subject country, known importers, importer/user associations and other interested parties, to inform them of the initiation of the subject investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules.
 - c. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, and to the Government of China, through its Embassy and to other interested parties who made a request in writing in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - d. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the mid-term review investigation to the known producers / exporters in the subject country, and other interested parties and provided them an opportunity to file response to the questionnaire in the form and manner prescribed within time limit (including the extended time limit), as prescribed in the initiation notification, and make their views known in writing in accordance with the Rule 6(4) of the Rules.
 - e. The Authority forwarded copies of the notification and non-confidential version of the petition to the known producers/ exporters.
 - f. The Government of China, through its Embassy in India was also requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the Embassy of China along with the details of the known producers/ exporters from China in accordance with the Rule 6(5) of the Rules.
 - g. In response to the above notification, the following producers/exporters from the subject country have filed response to the exporters’ questionnaire:
 - i. Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd.
 - ii. Zhejiang Coloray Technology Development Co., Ltd.
 - iii. Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd.
 - h. The Authority forwarded a copy of the notification and questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. Asian Paints Limited
 - ii. R.C. International

- iii. FX Pigments Pvt. Ltd.
 - iv. Kajal Chemicals
 - v. KPL International Limited
 - vi. Geochrome International
 - vii. Polychem Exports
 - viii. Kuncai International (India) Private Limited
- i. In response to the above notification, following related importer filed response to importer/user questionnaire responses.
- i. Kuncai International (India) Private Limited
- j. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April 2021 to 31st March 2022 (12 months).
- k. Transaction-wise imports data for the period of investigation and the preceding three years was procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and DG, Systems. The Authority has relied upon the data of DGCI&S for calculating the volume and value of imports of the subject goods in India and the data of DG, systems for comparison and reconciliation with the responses filed by the exporters.
- l. Further information was sought from the applicant and responding exporters/importers to the extent deemed necessary.
- m. All the interested parties were requested to e-mail non-confidential versions of their submissions/responses/comments filed by them to all the other interested parties.
- n. The non-injurious price (hereinafter referred to as “NIP”) has been determined based on the optimum cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the anti-dumping Rules. Such non-injurious price has been worked out so as to ascertain whether the anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- o. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held through video conferencing on 21st December 2022. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- p. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and information provided by various interested parties during investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been considered in this final finding.
- q. The Authority, during the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final finding, to the extent possible, and verified the data/documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and possible.
- r. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- s. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded this final finding based on the facts available in accordance with the Rule 6(8) of the Rules.
- t. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which have formed basis of the final finding was issued to the interested parties on 18th September, 2023 and the interested parties were given time till 23rd September to comment on the same. The comments on disclosure statement received from the interested parties have been considered to the extent found relevant in this final finding.

- u. '***' in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- v. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 USD = 75.34

C. Product under consideration and Like article

6. The product under consideration in the original investigation was

"7. The product under consideration in the present investigation is "Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade."

8. The product under consideration is chemically titanium dioxide coated micaceous and lustrous pearlescent pigment and is commercially known in the marketplace as Titanium Dioxide or Iron Oxide coated Mica Pearl Pigment or Pearl Lustre Pigments or Pearl Pigments. It is extensively used to impart colours and other effects such described as certain inorganic pigments/colouring agents giving lustrous/ shining frosted effects, such pearlescent effects, metallic effects, for coating, inks and plastics application

C.1 Submissions made by other interested parties

7. Following submission have been made by the interested parties

- i. The application states 'natural mica-based pearl industrial pigments' as the subject product. It is requested that the Authority clarify that the information provided in the application does not include cosmetic grade.
- ii. The scope of the PUC cannot be increased in an MTR investigation to include cosmetic grade. Reference is placed on Rule 23(1A), Notice of Initiation, and the written submissions of the applicant.
- iii. Without disclosure of the source of the subject imports, the assumption that industrial grade being imported as cosmetic grade seems to be a conjecture.
- iv. The allegation made by the domestic industry is merely assumption as import prices have decreased by mere 9% which can be due to raw material fluctuation.
- v. The domestic industry should have filed an anti-circumvention application to cover the situation where an article is being imported with altered description.

C.2 Submissions of the domestic industry

8. The subject goods are natural mica-based pearl industrial pigments excluding cosmetic grade. There are significant imports of cosmetic grade being imported for industrial application. It is requested that the Authority clarify that cosmetic grade for cosmetic application is exempted from the duty imposed.

C.3 Examination by the Authority

9. In the original investigation, the product under consideration was described as under:

"7. The product under consideration in the present investigation is "Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade."

8. The product under consideration is chemically titanium dioxide coated micaceous and lustrous pearlescent pigment and is commercially known in the marketplace as Titanium Dioxide or Iron Oxide coated Mica Pearl Pigment or Pearl Lustre Pigments or Pearl Pigments. It is extensively used to impart colours and other effects such described as certain inorganic pigments/colouring agents giving lustrous/ shining frosted effects, such pearlescent effects, metallic effects, for coating, inks and plastics application

10. The product scope is the same as that in the original investigation. The following PCNs methodology considered in the original investigation are adopted for the purpose of the subject investigation.

S.No.	Non-Automobile	Particle Size
1.	Silver- 1	Small (D50<17)- S Regular (D50 between 17-30)- R Large (D50>30)- L Special- X
2.	Gold- 2	Small (D50<17)- S

		Regular (D50 between 17-30)- R Large (D50>30)- L Special- X
3.	Iridescent- 3	Small (D50<17)- S Regular (D50 between 17-30)- R Large (D50>30)- L Special- X
4.	Earth tones (Bronze/ Copper/ Maroon)- 4	Small (D50<17)- S Regular (D50 between 17-30)- R Large (D50>30)- L Special- X
5.	Others- 5	Small (D50<17)- S Regular (D50 between 17-30)- R Large (D50>30)- L Special- X
Automobile application		
1.	Silver- 1	Small (D50<17)- S Regular (D50 between 17-30)- R Large (D50>30)- L Special- X
2.	Gold- 2	Small (D50<17)- S Regular (D50 between 17-30)- R Large (D50>30)- L Special- X
3.	Iridescent- 3	Small (D50<17)- S Regular (D50 between 17-30)- R Large (D50>30)- L Special- X
4.	Earth tones (Bronze/ Copper/ Maroon)- 4	Small (D50<17)- S Regular (D50 between 17-30)- R Large (D50>30)- L Special- X
5.	Others- 5	Small (D50<17)- S Regular (D50 between 17-30)- R Large (D50>30)- L Special- X

11. The subject goods are classified under Chapter 32 of the Customs Tariff Act under the tariff code 3206 11.
12. It is also noted that since the imposition of anti-dumping duties, the subject goods are being imported under different HSN codes apart from the dedicated code at 6-digit level, namely, 32064990, 32061900, 32041759, 32041739, 32041720, 32041790 and 32071040. The Authority notes that the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
13. The present investigation is a mid-term review, limited in scope to examining the need for re-quantification of dumping margin and injury margin, and modification of duty. The scope of the review does not include re-examination of the product scope. Therefore, the scope of the product under consideration in the present review shall be the same as that in the previous investigation.
14. The Authority notes the submissions of the interested parties regarding the scope of the product under consideration. The cosmetic grade was excluded from the product under consideration in the original investigation and the same is also excluded from the current investigation. Some of the interested parties have sought clarification regarding exclusion. It is clarified that the cosmetic grade means *Natural Mica based Pearl Industrial Pigments*. It is further noted that this clarification does not tantamount to modification of product scope. There is no change in scope of product under consideration.
15. The Authority notes that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from China are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two

interchangeably. The same has not been disputed by other interested parties as well. In view of the same, the Authority concludes that the goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject country.

16. The other interested parties have raised the issue that the domestic industry should have filed an anti-circumvention application to cover the situation where an article is being imported with altered description. The Authority notes that this is not a case of anti-circumvention as the articles are not being imported with altered description rather the imports have increased under certain PCNs and decreased in the others.

D. Domestic Industry and Standing

17. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

18. The application has been filed by Sudarshan Chemical Industries Limited, who is the sole producer of the product under consideration in India. It is noted that the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production. The applicant is neither related to subject Chinese producers or exporter nor importer of the subject goods in India. Therefore, the Authority holds that Sudarshan Chemical Industries constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) read with rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.
19. No submissions have been advanced by the applicant or the other interested parties with regards to the standing of the domestic industry.

E. Scope of Review

E.1 Submissions made by other interested parties

20. Following submission are made by the other interested parties:

- i. The scope of Rule 23(1A) is limited and does not empower the Authority to carry out limited review. No limited review has been initiated by the Authority in the recent past. Reference is placed on Manual of Operating Practises for Trade Investigations and closure letter issued in imports of Jute products on 28 March 2019.
- ii. Rule 23(1A) only empowers the Authority to withdraw existing duties and not enhance under any circumstances. Reliance cannot be placed on Indian Graphite Manufacturers Association v. Ministry of Finance & Ors (13 April 2006) as the decision was limited to SSR investigation.
- iii. Rule 23 (1A) does not bind the Authority to initiate review limited to Kuncai as requested by the applicant. The Authority is empowered under the provision to define the scope of the review. Considering the applicant made no objection to the initiation against all producers/ exporters, the same cannot be challenged before the Authority at present.
- iv. Reliance on the OM dated 18 June 2019 by the applicant is misplaced as the same was issued in the context of Rule 23 and not Rule 23(1A), The latter explicitly requires injury examination. The OM has to be read in the context of the issue and cannot supersede the Rules. The Authority’s practice is not to initiate investigations based on requests for limited review.
- v. Reliance placed on mid-term review investigation on aluminium alloy road wheels from China PR dated 30 August 2022 is incorrect as the facts of the case is distinguished from the present investigation.
- vi. Reliance placed on *Rishiroop Polymers* is incorrect as the ratio of the decision is only regarding the withdrawal of duty which does not lead to the conclusion that the other parameters are not required to be examined.
- vii. The real reason for the applicant seeking to avoid redetermination of dumping or injury margin for other producers is because they are facing quality issues, have limited production capability which makes it necessary for them to import the product to retain their market share.
- viii. Coloray and Lingbao does not dispute that Rule 23(1A) permits the Authority to conduct limited review. Rule 23(1A) permits the Authority to initiate review against all producers from China PR. Reliance is placed on WTO panel report in United States — *Anti-Dumping Measures on Certain Shrimp from Viet Nam* (WT/DS/429/R).

E.2 Submissions of the domestic industry

21. Following submission are made by the domestic industry:

- i. Changed circumstances in the POI warrant the need for re-quantification and enhancement of existing anti-dumping duty in force on natural mica-based pearl industrial pigments excluding cosmetic grade exported from Fujian Kuncai Material Technology Company Limited.
- ii. Rule 23 (1A) read with OM dated June 18, 2019 permits limited review of dumping margin and injury margin. Reliance is also placed on *Rishiroop Polymers Pvt Ltd v. Designated Authority and Addl. Secretary*² and MTR investigation on imports of *Aluminium Alloy Road Wheels from China PR*, (dated 30th August 2022).
- iii. Review of all other exporters shall cause prejudice to the non-participating Chinese producers and increase burden on DGTR. No *prima facie* evidence is on record to show changed circumstances *qua* these exporters.
- iv. Manual of Operating Practises for Trade Investigations cannot be cited in case of contradictions/ differences as mentioned in Page xi of the Manual. It allows the Authority to recognise case-specific variations in different investigations and final decisions are to be made based on merits.
- v. As regards the argument that Rule 23(1A) only empowers the Authority to withdraw duty, reliance is placed on the CESTAT decision in *Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. v. Designated Authority (2010(253) ELT 564 (Tri-Del.))*. It was held that the purpose for which the statute authorises the levy; it also has the incidental and ancillary power to increase or reduce the same to make it fully effective against dumping.

E.3 Examination by the Authority

22. The present investigation was initiated as per Rule 23(1A), which, inter-alia, provides as follows:

“(1A) The designated authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.”

23. The Authority issued an Office Memorandum dated 18th June 2019 providing for review, which, inter-alia, provides as follows:

“6. Any interested party, including domestic industry, can seek a review under rule 23 and 24 of AD and CVD Rules respectively to alter the quantum or form of existing AD/ CVD duty. The changed circumstances which may warrant a review may include changes in raw material prices, costs, duty structure, exchange rate etc. The Authority would consider a fresh POI for such a review and evaluate all key parameters viz dumping margin or subsidy margin, injury margin and landed value for this chosen POI. The modified AD/ CVD, including the form, would be based on this comprehensive re-computation.”

24. The Authority notes that the present review has been initiated based on change in circumstances alleged by the applicant. The present investigation is limited to examination of whether there has been a change in circumstances which justify the modification of the quantum of anti-dumping duty. In their application, the applicant had alleged the following;

- a. There is significant shift in the product profile exported by the exporter to the Indian market. The increase in costs on account of raw materials is not proportionately reflected in the increase in the export price.
- b. The export price of some PCNs has increased less than raw material price increase.
- c. The weighted average increase in export price for few PCN is negative, whereas the weighted average increase in costs is positive.

25. Some of the interested parties have contended that the scope of Rule 23(1A) is limited and does not empower the Authority to either carry out a limited review or enhance duties. It is noted that it has been the consistent practice of the Authority to vary the duty rates by either reducing or enhancing or retaining the quantum of duty during a mid-term review. The Authority notes that it has conducted reviews for re-quantification of duty under Rule 23 in the past as well. One of such review, concerning imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) was challenged before the Hon'ble Supreme Court, and was found consistent with the provisions of Rule 23 by the Apex Court.

26. 2 Further in the recent MTR investigation on imports of Aluminium Alloy Road Wheels from China PR, dated 30th August 2022, the Authority has conducted review limited to re-examination of the dumping/injury margin. Therefore, the present review cannot be considered to be beyond the provisions of Rule 23.

² (2006 (196) E.L.T. 385 (SC)),

27. Further, the Designated Authority has vide Office Memorandum dated 18th June 2019, issued a guideline stating that any interested party, including the domestic industry, could seek initiation of a review under Rule 23 to alter the quantum or form of duty.
28. Further, Rule 23(1) mentions that "any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury." The meaning of the word "to the extent" means the duration or degree of duty. Further Rule 23(1) provides for "if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted". Thus, this rule allows the Authority to vary the degree (quantum) of duty.
29. In view of the foregoing, the Authority concludes that the scope of the present review is limited only to examination of the need for re-determination of dumping margin/ injury margin for all exporters subjected to the duties in the earlier investigation. The scope of such review is governed by the provisions of Rule 23, read with Office Memorandum dated 18th June 2019.
30. The Authority notes that the applicant had sought review limited to M/s. Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd (Kuncai). The Authority refers to the WTO panel report in US – *Shrimp II (Viet Nam)* [WT/DS429/R], wherein it has been held that the Authority is vested with the discretion to undertake a review on an order-wise or on a company-specific basis. Such decision depends on both the specific request made by the interested party and the evidence submitted by the party substantiating the need for a review.
31. In the present case, the request of the applicant for a limited review of duty imposed on only one exporter from China based on the submitted evidence was not sustainable, as the changed circumstances claimed by the applicant would also have affected the export price and cost of production of other exporters from China. The applicant had not submitted any evidence as to why/how the changed circumstances are applicable only to Kuncai and not to the other exporters of the subject goods from China PR. In light of the same, the Authority has undertaken the current review of the duty for all exporters/producers after being satisfied that the change in circumstance including cost of raw material and export price alleged by the applicant requires to be investigated for all producers/exporters in the subject country.
32. With respect to the contention raised by the domestic industry that there has been increase in cost of raw materials but there is no proportionate increase in the export price, the Authority notes that as per the data submitted by the domestic industry it is observed that increase in the price of raw material in certain PCNs is more than the increase in the export price during the period of review in comparison to period of original investigation. On further analysis it is seen that the increase in average cost of major raw material used in the manufacturing of product under consideration is more than the increase in average landed value of the product under consideration during the period of review as compared to the period of original investigation.
33. The table below demonstrate the said trend:

Particulars	2020-2021 (Rs./Kg)	2021-2022 (POI) (Rs./Kg)	Increase/Decrease (%)
Cost of major raw material	***	***	***
Indexed	100	124	20-30
Landed Value	***	***	***
Indexed1	100	112	10-20

The Authority after analysing the data concludes that increase in cost of major raw materials has impacted the injury parameters which is detrimental to the interest of the domestic industry. Therefore, there is a need to review the dumping margin and injury margin.

F. Confidentiality

F.1 Submissions made by other interested parties

34. The applicant has claimed excessive confidentiality on the source of the import data. Reliance is placed on Mono Ethylene Glycol from Kuwait, Saudi Arabia, and USA (27 October 2022) and CESTAT order in vitrified Tiles.

F.2 Submissions of the domestic industry

35. Non-disclosure of analysis on PCN and export data is due to the prohibition placed by Section 135AA of the Customs Act read with Trade Notice 01/2022. The confidentiality claims of the domestic industry are in adherence with Trade Notice 1/2013.

F.3 Examination by the Authority

36. With regard to confidentiality of the information, the Rule 7 of the Anti-dumping Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

37. The Authority considers that any information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis by the parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.

38. As regards import data filed in the application, the import data received from market intelligence sources cannot be shared as publishing of such data is prohibited under Section 135AA of the Customs Act, 1962 “unless required so to do under any law for the time being in force”. The data is being provided in the application in terms of the provisions of Rule 5(2) read with the Trade Notice issued in this regard, specifying the application formats. Hence, the confidentiality claim of the applicant on the import data has been accepted by the Authority.

39. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by the interested parties by directing the interested parties to share the non-confidential version of their submissions with each other through e-mails.

40. Some of the interested parties have contended that the domestic industry has not shown good cause for confidentiality. The Authority notes that the domestic industry has provided a justification table in the non-confidential version of the petition. The Authority has accepted the confidentiality claimed by all the interested parties after being satisfied about the same.

G. Miscellaneous

G.1 Submissions made by other interested parties

41. The following submissions have been made by the interested parties

- i. Export details of the subject goods are not available in the public domain and circulation of the same is violative of Section 135AA of the Customs Act. The applicant has not provided the source and authenticity of the data submitted. The applicant has either filed fabricated information or the same has been procured illegally.

G.2 Submissions of the domestic industry

42. The following submissions have been made by the domestic industry-

- i. The export details of the subject goods have been procured from market intelligence. The allegations made by the respondent on the accuracy and veracity of the same is baseless.

G.3 Examination by the Authority

43. As regards the contentions on the export data submitted by the Domestic industry, the Authority notes that the data provided by the domestic industry does not affect the findings of the Designated Authority as the Authority relied on DGCI&S and DG system data.

H. Normal value, Dumping margin

H.1 Submissions made by other interested parties

44. The following submissions have been made by the interested parties

- i. The average raw material cost per unit of the subject goods by Kuncai has declined and the export price increased during the POI as compared to the POI of the original investigation.
- ii. The domestic industry has failed to establish with evidence the extent of increase in the raw materials price. The increase in the raw material cost is applicable to all producers and hence the review should not be limited to Kuncai.
- iii. Zhejiang Coloray Technology Development Co., Ltd should not be granted individual duty. Reliance is placed on TDI Review Investigation and Jute Review Investigation.

H.2 Submissions of the domestic industry

45. The following submissions have been made by the domestic industry.

- i. There is a change in the product sales mix sold during the POI of the original investigation and the current POI. PCN wise analysis in the original investigation was undertaken which shows that change in the sales mix of the current period of investigation has impacted the dumping and injury margin warranting a review of Kuncai.
- ii. Proportional increase in the export price is not commensurate to increase in cost of raw material. Rather, there is a reduction in export price for certain PCN, despite increase in raw material cost.
- iii. The Authority may determine normal value on the basis of cost of production, duly adjusted as done in the original investigation.
- iv. As regards the decline in raw material cost per unit of Kuncai, it is submitted that there is no relevance for the same in the present investigation as Kuncai (China) is a non-market economy as determined in the original investigation.
- v. Change in circumstance due to change in raw material cost cannot be assumed for all exporters as the same has not been supported with evidence.
- vi. The dumping duty should not be modified for other companies as no changed circumstances have been established for them.

H.3 Examination by the Authority

46. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR has filed the supplementary questionnaire response to rebut the presumptions as mentioned in para 8 of Annexure – I of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure – I of the Rules as under.

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

47. The Authority notes that no producer or exporter from China PR has submitted market economy treatment or supplementary questionnaire response. The normal value computation for these producers/exporters are thus required to be determined in terms of provisions of para 7 of Annexure-1 of Anti-Dumping Rules. The Authority notes that under the provisions of para (7) of Annexure – I, the normal value may be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country, or the price of exports from such a third country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.
48. In the present case, none of the interested parties have claimed or provided information with regard to price or constructed value in a market economy third country, or the price of exports from such a third country to other countries, including India. Further, the domestic industry has not proposed an alternate surrogate country for China PR. In light of, the same, the Authority concludes that there is no sufficient information to consider application of the first proviso of para 7 nor is any information available with the Authority for the same.
49. The Authority also notes that the trade map data of PUC exports to other countries does not have details about the PCNs prescribed by the Authority. Also, the PUC does not have a dedicated HSN Code. Therefore, in absence of sufficient information on export of PUC to other country, the Authority cannot adopt option 2 of para 7.

50. The Authority, therefore, has determined normal value based on other reasonable basis. For this purpose, the Authority has considered the cost of production of the domestic industry, with due adjustments, and a reasonable addition of selling, general and administrative expenses, and profits.

H.4 Determination of the Export Price

51. The following producers/exporters from China PR have filed response to the Exporter's questionnaire:

- a. Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd
- b. Zhejiang Coloray Technology Development Co., Ltd.
- c. Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd

a. Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd

Export Price

52. Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd. has directly exported ***MT subject goods to both unrelated and related customers in India of an invoice value of US\$ ***. The related importer has cooperated with the investigation. To ensure that the related transactions are at arms-length, from the response filed by the related importer, it is seen that the sales made by the importer shows profit. Accordingly, after allowing the adjustment on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port, and other related expenses etc., the weighted average ex-factory export price and weighted average landed value comes to ***US\$ / MT and ***US\$ / MT respectively.

b. Zhejiang Coloray Technology Development Co., Ltd.

Export Price

53. During the period of investigation, Zhejiang Coloray Technology Development Co., Ltd. has directly Exported ***MT of product under consideration to unrelated customers in India of an invoice value of US\$ ***. After allowing the adjustment on account of ocean freight, inland transportation, insurance, port, and other related expenses etc., the weighted average ex-factory export price and weighted average landed value comes to US\$ ***/MT and ***US\$ / MT respectively.

c. Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd

Export Price

54. During the period of investigation, Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd has directly exported ***MT of product under consideration to unrelated customers in India of an invoice value of US\$ ***. After allowing the adjustment on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port, and other related expenses etc., the weighted average ex-factory export price and weighted average landed value comes to ***US\$ / MT and ***US\$ / MT respectively.

d. Other non-cooperative exporters from China subject to investigations

55. The export price for non-cooperative producers/exporters who have not cooperated with the present investigation is considered based on the import price available on record, considering the data provided by the cooperative producers/exporters and imports into India, in accordance with Rule 6(8) of the Rules. The export price so determined is mentioned in the dumping margin table.

Dumping Margin

56. The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation can be seen from the table below. It would be seen that there is a change in dumping margin.

Dumping Margin Table

Producer/Exporter	Normal Value (USD/MT)	Net Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd	***	***	***	***	10-20
Zhejiang Coloray Technology Development Co., Ltd.	***	***	***	***	70-80
Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd	***	***	***	***	70-80

Non-cooperative producers/ exporters	***	***	***	***	90-100
---	-----	-----	-----	-----	--------

I. Injury

I.1 Submissions made by other interested parties

57. The following submission are made by the other interested parties

- i. The applicant has failed to meet the precondition of 'lasting nature of the changed circumstances' as necessitated by the Manual of Operating Practises for Trade Remedy Investigations. Reliance is placed on Carbon Black (dated 28 February 2013) and closure letter in TDI.
- ii. The applicant has not suffered injury on accounts of subject imports as there has been 17% increase in the installed capacity, 22% increase in capacity utilization, 40% increase in production, 32% increase in domestic sales, 5.5% increase in export sales, increase in the domestic sales price, increase in productivity per day by 40%.
- iii. There is no causal link as there is increase in capacity, interest cost, depreciation and decline in exports sales.
- iv. Given the increase in interest cost, and depreciation, the Authority should make adjustment for cost incurred as start-up costs, extra-ordinary costs, non-recurring cost, and excess depreciation.

I.2 Submissions of the domestic industry

58. The following submission are made by the domestic industry.

- i. There is no requirement to show lasting nature of the changed circumstances as per the Anti-dumping Agreement, AD Rules and the application proforma.
- ii. The Authority's practice is to examine lasting nature in the event of revocation of anti-dumping duty. Reliance is placed on mid-term review on the imports of "4,4Diamino Stilbene2, 2 Disulphonic Acid" (DASDA), originating in or exported from China PR (dated 26th September 2016).
- iii. The changed circumstance alleged by the applicant is reflective of one year and has impacted the dumping and injury margin previously determined. Hence, they are enough to show that the change is of lasting nature.
- iv. As regards arguments on injury, it is submitted that the current investigation is limited redetermination of the dumping margin and injury margin previously determined and quantum of duties levied in the original investigation.

I.3 Examination by the Authority

59. Some of the interested parties have claimed that the Authority should examine injury to the domestic industry. The Authority notes that the present investigation was initiated to re- determine the quantum of anti-dumping duty levied on all exporters from the subject country. The request of the applicant for a limited review of duty imposed on only one exporter from China.

60. Further, the domestic industry had not made any claims with regard to the injury being caused due to dumped imports. The Authority notes that since the present investigation is limited mid-term review initiated for re-quantification of anti-dumping duty levied on subject exporters from the subject country, the Authority has re-quantified the dumping margin and injury margin imposed on the exporters in the original investigation. However, the Authority has examined the injury parameters for a more comprehensive investigation.

61. Some of the interested parties have contended that the lasting nature of the changed circumstance has not been established. The Authority has previously noted the following in 4,4Diamino Stilbene2, 2 Disulphonic Acid" (DASDA), originating in or exported from China PR, dated 26th September 2016;

"The language of the rules concerning sunset review and midterm review has been deliberately kept different so as to emphasize more on the cautiousness of establishing the need for withdrawal. The emphasis on word "not" likely in Rule 23 (1A) of AD Rules, signifies a higher and stringent obligation while examining premature withdrawal of antidumping duty."

62. The Authority notes that such stringent obligation arises only when examining premature withdrawal of the anti-dumping duty. In addition, the Authority has initiated the present investigation after being satisfied of the *prima facie* evidence submitted by the applicant. The Authority notes that the applicant has substantiated the changed circumstance by providing information for a period of one year.

63. The Authority has examined the injury information over the injury period. Having satisfied that the changed circumstance alleged by the applicant is reflective of one year and has impacted the dumping and injury margin previously determined, the Authority deems that they are enough to show that the change is of lasting nature. The

Authority notes the fact that the injury to the domestic industry has continued over the entire injury period which further shows that the changed circumstances are of lasting nature.

64. The Authority also notes that it is not necessary that all parameters of injury must show deterioration. Some parameters may show deterioration, while others may not. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties. Further, since anti-dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers that the impact of existing duties on the subject imports is required to be considered while examining the injury to the domestic industry. The Authority has examined whether the existing measure is not sufficient to counteract the dumping which is causing the injury.

I-4 Volume effect of dumped imports on the domestic industry

a. Assessment of demand/ apparent consumption

65. For the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the subject goods in India has been defined as the sum of the domestic sales of the domestic industry in India and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

SN	Particulars	Units	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	93	91	125
3	Imports from China PR	MT	1,841	2,003	2,471	1,871
4	Imports from other countries	MT	231	178	192	294
5	Total demand/consumption	MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	101	115	112

66. It is seen that the demand for the PUC has increased over the first three years of the injury period with a marginal decline in the POI, as compared to the immediately preceding period. Overall, the demand has increased over the injury period.

b. Import volume from the subject countries

67. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports from the subject country, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The same is analysed as follows:

SN	Particulars	Units	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1)	China PR	MT	1,841	2,003	2,471	1,871
2)	Other countries	MT	231	178	192	294
3)	Total imports	MT	2,072	2,181	2,663	2,166
4)	Subject country in relation to-					
i.	Indian production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	117	165	85
ii.	Demand	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	108	117	91
iii.	Total imports	%	89	92	93	86

68. It is seen that:

- The volume of imports from the subject countries have increased until 2020-21 but has declined in the POI due to imposition of anti-dumping duties in August 2021. The sales of the domestic industry has increased during period of investigation as compared to the previous year.
- Despite imposition of anti-dumping duties in existence, the imports from China PR holds major share in Indian demand and total imports into India.

I-5 Price effect of dumped imports on the domestic industry

69. With regard to the effect of the dumped imports on the prices of the domestic industry, it is required to be examined whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent the price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined through price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, and net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the imports of the subject goods from the subject country.

a) Price undercutting

70. For the purpose of the price undercutting analysis, the net sales realization of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country work out as follows:

SN	Particulars	Units	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1)	Net sales realisation	Rs/MT	***	***	***	***
2)	Landed Price	Rs/MT	3,80,425	3,79,897	3,94,105	4,43,452
3)	Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
4)	Price undercutting	%	***	***	***	***
5)	Price undercutting	Range %	25-35	20-30	10-20	0-10

71. The Authority notes that the price undercutting is significant and positive despite the existence of the anti-dumping duties.

b) Price suppression and depression

72. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress such prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are examined as below:

SN.	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Cost of Sales	Rs. /MT	***	***	***	***
	Trend		100	101	105	108
2)	Selling Price	Rs. /MT	***	***	***	***
	Trend		100	93	91	94
3)	Landed Price	Rs. /MT	***	***	***	***
	Trend		100	100	104	117

73. It is seen that the landed price of imports from the subject country continues to be below the cost of sales of the domestic industry. Consequently, the domestic industry is unable to increase its selling price even at the level of cost in the year 2020-21 and period of investigation, despite anti-dumping duties in existence. The dumped import from subject country is suppressing the prices of the domestic industry.

I-6 Economic Parameters of the domestic industry

74. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively considering various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a) Capacity, production, capacity utilization and domestic sales

75. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	117
Production	MT	***	***	***	***

<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>93</i>	<i>81</i>	<i>119</i>
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>93</i>	<i>81</i>	<i>102</i>
Sales (Domestic)	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>93</i>	<i>91</i>	<i>125</i>

76. It is seen that the capacity of the domestic industry has increased during POI. The production, capacity utilisation and domestic sales have increased during POI. The increase is due to anti-dumping duty in existence.

b) Profitability, return on investment and cash profits

77. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Profit/(Loss) per unit	Rs./MT	***	***	(***)	(***)
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>6</i>	<i>-58</i>	<i>-54</i>
Profit/Loss	₹ Lacs	***	***	(***)	(***)
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>6</i>	<i>-53</i>	<i>-68</i>
Cash Profit per unit	Rs./MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>48</i>	<i>14</i>	<i>9</i>
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>45</i>	<i>12</i>	<i>11</i>
PBIT per unit	Rs./MT	***	***	(***)	(***)
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>12</i>	<i>-35</i>	<i>-34</i>
PBIT	₹ Lacs	***	***	(***)	(***)
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>11</i>	<i>-32</i>	<i>-43</i>
Return on Capital Employed	%	***	***	(***)	(***)
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>13</i>	<i>-49</i>	<i>-48</i>

78. It is seen that:

- The domestic industry is suffering losses during POI despite anti-dumping duties in existence.
- The domestic industry is unable to increase its cash profits, PBIT and ROI at levels achieved in 2018-19 and in 2019-20. The return on investment of the domestic industry is below 1% in 2020-21. The domestic industry is unable to improve its performance even after imposition of anti-dumping duties, due to imports entering in the Indian market at an unfair price that current anti-dumping duties are unable to address.

c) Inventories

79. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Stock (Volume)	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Closing inventory	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>142</i>	<i>127</i>	<i>132</i>

80. It is noted that the average inventory held by the domestic industry increased during the POI.

d) Employment, wages, and productivity

81. Employment, wages, and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
No of Employees	Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>91</i>	<i>99</i>	<i>108</i>

Productivity per day	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	100	75	125
Productivity per Employee	MT/Nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	100	85	108
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	116	92	119

82. It is seen that the number of employees, productivity and wages paid have increased during POI as compared to previous year as well as base year.

e) Magnitude of dumping

83. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the dumped imports are causing injury to the domestic industry. The data shows that the dumping margin determined against the subject country has increased as compared to the previous investigation.

f) Ability to raise capital investment.

84. The domestic industry is suffering financial losses and has not been able to earn a positive contribution. Due to the dumped imports, the operations of the industry have been adversely impacted.

I.7 Magnitude of Injury Margin

85. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities, and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered in order to nullify injury, if any, caused by the domestic industry by in efficient of raw material and utilisation. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax return towards interest, profit, and taxes in order to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

86. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters.

87. Based on the landed price and the non-injurious price determined as above, the injury margin for the producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below.

Injury Margin Table

Producer/Exporter	NIP (USD/MT)	Landed Value (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range)
Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd	***	***	***	***	0-10
Zhejiang Coloray Technology Development Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd	***	***	***	***	40-50
Non-cooperative producers/exporters	***	***	***	***	60-70

J. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

88. The Authority is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices and competition between the foreign and the domestic producers, developments in technology and the export

performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether the above said factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a. Volume and prices of imports from third countries

89. The imports from other countries are either at higher prices or at negligible levels.

b. Contraction in Demand

90. It is noted that demand has increased as compared to the base year.

c. Changes in the pattern of consumption

91. There have been no changes in the pattern of consumption.

d. Trade restrictive practises

92. There is no known trade restrictive practice.

e. Development in technology

93. None of the interested parties has furnished any evidence to demonstrate any change in the technology.

f. Export performance of the domestic industry

94. The Authority notes that the injury information examined relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market.

g. Performance of other products of domestic industry

95. The Authority has considered data only in relation to the product under consideration

h. Productivity of the domestic industry

96. The domestic industry has provided the data relating to their productivity.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS

L.1 Submissions made by other interested parties

97. The following submission are made by the other interested parties

- i. There are certain discrepancies in the calculations of the Coloray's PCN-wise Landed Value whereby the landed prices for certain PCNs appear to have been inadvertently interchanged.
- ii. The Authority has not clarified which PCNs of the domestic industry were selected for comparison with the Coloray. The Authority must clarify the same as otherwise, it is a violation of the principle of natural justice.
- iii. Neither has the petitioner made any submission regarding injury nor does the initiation notification covers the scope of the present review on injury faced by the petitioner. The Authority should not undertake injury examination.
- iv. It is a violation of natural justice for the Authority to have analysed the the petitioner's data and allegations regarding alleged injury without first having provided an opportunity to the other interested parties to comment on the same.
- v. The volume of the subject imports has decreased significantly during the POI and are insignificant even in the injury period. The petitioner has deliberately reduced its selling price to show adverse effects of the subject imports.
- vi. The petitioner's capacity, production, capacity utilization and domestic sales volume has increased during the POI as compared to the injury period. Financial losses suffered is attributed to increase in fixed assets and depreciation costs.
- vii. There is no causal link between dumped imports and injury, the domestic industry is suffering losses during the POI in spite of anti-dumping duties in existence.
- viii. The magnitude of dumping has decreased substantially in the present review investigations as compared to the original investigation, the Authority had determined the dumping margin of all other producers to be in the range of 200-300% whereas in the present mid-term review investigation, the margin is just 90-100%.
- ix. Rule 23(1A) does not empower the Authority to carry out a limited mid-term review. The same was held by the Authority when closing the request for initiating a mid-term review of the anti-dumping duties imposed on Jute products.

- x. Change in the product profile in exports claimed by the applicant is misleading, fabricated, and based on fudged information, or procured through illegal means as this detail/information: (a) is not available in public domain, (b) is not available in transaction-wise data, (c) were not provided by the applicant in its application, and (d) is only available in the questionnaire response filed by the responding exporter.
- xi. The applicant must disclose the source of export details, and if it is found to be procured through illegal means, or fabricated, the investigation must be terminated.
- xii. Rule 23(1A) empowers the Authority to only withdraw the duties (partial or complete) and not increase the same under any circumstances.
- xiii. The present investigation is without jurisdiction as the initiation notification nor the application provides information as to how the changed circumstances are of lasting nature. The application is completely in violation of the provisions of Rule 5 of the anti-dumping rules.
- xiv. The claims made by the applicant regarding increase in the raw material and export price of the responding exporter are wrong, misleading, fabricated and incorrect as: (a) the average raw material cost per unit of the subject goods of the responding producer / exporter declined by 3.64% during the POI as compared to the POI of the original investigation, and (b) the average export price of the responding exporter increased significantly during the POI as compared to the POI of the original investigation i.e., by around 7%.
- xv. Merely providing information for a period of one year does not substantiate that the changed circumstances are of lasting nature.
- xvi. Increasing duty will be against public interest as the applicant is the only producer creating monopolistic situation, they are strongly export oriented and unable to meet the domestic demand resulting in demand supply gap.
- xvii. It is the consistent practice of the Authority to consider the nearest PCNs of the domestic industry for those PCNs which were exported by the producers / exporters during the POI but not manufactured and / or sold by the domestic industry in commercial quantities during the POI.

L.2 Submissions of the domestic industry

98. The following submission are made by the domestic industry.

- i. The domestic industry sought limited review against one exporter. Widening the scope of the investigation without sufficient grounds and based on the hypothesis that the changed circumstance claimed by the domestic industry is likely to have affected other exporters is mere presumption.
- ii. Examination of injury parameters is not warranted in a case limited to re-quantification of anti-dumping duty levied in the original investigation.
- iii. Lasting nature is established in cases filed for premature withdrawal of anti-dumping duties. None of the exporters have disputed with evidence that the changed circumstances are not lasting in nature.
- iv. All 9 HSN codes under which the product under consideration is being imported into India is to be included within the duty table.
- v. Exclusion in the current investigation is only of cosmetic grade for cosmetic application. Clarifying the same does not amount to broadening the scope of the product under consideration.
- vi. The volume of consumption of certain raw materials have varied over the injury period. The Authority is requested to not optimise them for NIP determination.
- vii. NIP law provides for normation of consumption inefficiencies and not difference in consumption. The Authority should give detailed findings if rejecting the claims of domestic industry regarding NIP.
- viii. As the domestic industry has not supplied identical PCNs to those exported by the foreign producers, the Authority should construct NIP for comparable PCNs and make due adjustments for differences in physical characteristics of the product. Reliance is placed on India's WTO proposal.
- ix. The Authority should recommend residual duties to the producers/exporters who are non-cooperating in the present investigation.
- x. The domestic industry was never burdened with the responsibility to evidence that changed circumstance is applicable only to Kuncai at any stage of this investigation. It lies with the exporters who have cooperated in the investigation to adduce the evidence.

L.3 Examination by the Authority

99. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
100. On the submissions made by the domestic industry regarding widening the review to include all exporters from the subject country, the Authority notes that it is the prerogative of the Authority in deciding whether to extend the scope of the review on an order-wise or on a company-specific basis. In the present investigation, the Authority has undertaken the current review of the duty for all exporters/producers after being satisfied that the change in circumstance including cost of raw material and export price alleged by the applicant requires to be investigated for all producers/exporters in the subject country. Further, from the responses filed by the producers/exporter, the Authority has been satisfied that the prices of the subject goods have not been aligned with the changes of cost of production.
101. Both the domestic industry and respondents have contended that injury examination need not be conducted for an investigation with limited scope, the Authority notes that even though the present investigation is limited mid-term review initiated for re-quantification of anti-dumping duty levied on subject exporters from the subject country, the Authority has examined injury parameters to ascertain the lasting nature of the changed circumstances.
102. The other interested party has cited natural justice violation when stating that they were not afforded an opportunity to comment on the injury parameters of the domestic industry until the stage of disclosure statement. On the direction of the Authority, the domestic industry has duly submitted their injury formats and shared a non-confidential version of the same as addendum to their application on 16 December 2022. The other interested parties have been provided ample time to examine and provide their comments on the same. Further, the comments on injury parameters have been addressed under the relevant headings.
103. The submissions regarding the inclusion of HSN codes in the duty table has been noted and the same has been included in the table below.
104. All submissions made on the scope of Rule 23(1A), lasting nature, changed circumstance that resulted in the initiation of the investigation, the veracity of the export data submitted by the domestic industry, and public interest and clarification on the product scope have already been addressed under the relevant headings.
105. As regards the issues raised by the domestic industry on the construction of NIP for comparable PCNs and adjustment for differences in physical characteristics and other issues on NIP determination. In this regard, firstly, the Authority matched PCN to the PCN and wherever not matched, considered the nearest NIP for those PCNs which are not produced by the domestic industry, as per DGTR consistent practice. It is also noted that the product category /profile is same. The same methodology was adopted by the Authority in the original investigation.
106. As regards discrepancies in the calculations of the Coloray's PCN-wise Landed Value, the same has been corrected for the purpose of the present findings.
107. As regards the argument on disclosure if PCNs of the domestic industry were selected for comparison with the Coloray, the Authority has undertaken its consistent practice. Where the domestic industry has supplied the exact similar PCN, the same has been considered for present determination. However, in cases where the import quantities include some of the PCNs, which have not been produced by the domestic industry during the period of investigation, the non-injurious price or normal value for these PCNs have been computed based on the closest PCN with due adjustments, if required.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

L.1 Submissions made by other interested parties

108. The following submission are made by the other interested parties

- i. Enhancement of duty will be against the public interest as the applicant is export oriented, there is huge demand-supply gap, and creates a monopolistic situation.

L.2 Submissions of the domestic industry

109. The following submission are made by the domestic industry.

- i. As regards the contention on public interest, reference is placed on the analysis conducted by the Authority in the original investigation where it did not find any adverse impact of the duty on the consumers. Further, there are no consumer/user participation in the current investigation.

L.3 Examination by the Authority

110. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers, and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide

relevant information with respect to the present investigation, including the possible effects of enhancement of existing anti-dumping duties on their operations. The Authority sought information on, *inter-alia*, the interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the consumers to switch sources, the effect of anti-dumping duties on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation resulting from modified anti-dumping duties. None of the users or importers of the product under consideration has responded to the initiation notification or filed response to the questionnaire.

111. It is noted that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by unfair trade practises of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority recognised that the modification of the anti-dumping duties might affect the price levels of the subject goods as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India.
112. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by imposition of anti-dumping measures, but would prevent the decline of the domestic industry that may ensue because of low-prices subject imports from the subject country and help maintain the wider availability of choices to the consumers of the subject goods.
113. On the issue of monopolistic behaviours of the domestic industry, it is noted that the purpose of anti-dumping duty is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market. From the anti-dumping rules, it is not borne out that a company, even if a monopoly, is prohibited from requesting the Authority for action against the unfair imports. In the instant case, the fact that there is only one Indian producer of the product under consideration and non-imposition of anti-dumping duty will adversely impact the indigenous production of the product concern and the fact that the impact of anti-dumping duty is miniscule to the consumers of the product under consideration as noted in the final findings of the original case, the Authority is of the view that the imposition of anti-dumping duty will be in public interest.

M. CONCLUSION

114. After examining various submissions of the interested parties with regard to product under consideration, confidentiality, adequacy and accuracy of the application, questionnaire responses, scope of the investigation, re-quantification of dumping and injury margin, other factors allegedly causing injury to the domestic industry, the Authority notes that it has appropriately dealt with the issues raised in the relevant paragraphs of these findings. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
 - i. The product scope and the PCN methodology considered in the present investigation remains the same as defined in the original investigation. It is clarified that the exclusion from the product scope is *Natural Mica based Pearl Industrial Pigments* excluding cosmetic grade.
 - ii. The subject goods do not have a dedicated code at 8-digit level and is being imported under various HSN codes which are covered within the scope of this findings.
 - iii. The applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
 - iv. The scope of the present investigation is governed by provisions Rule 23(1A) read with the Office Memorandum dated 18th June 2019 and is limited to re-determination of dumping/injury margin for all exporters subjected to duties in the earlier investigation.
 - v. The dumping margins of the cooperating exporters are more than *de minimus*.
 - vi. The Authority has examined the injury parameters for a more comprehensive investigation even though the present investigation is limited to re-quantification of anti-dumping duty levied in the original investigation.
 - vii. The lasting nature of the changed circumstance has been duly established by the domestic industry.

N. RECOMMENDATION

115. The Authority notes that the mid-term review investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic producers, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link.
116. Having concluded that there is changed circumstance warranting modification of the existing duties, the Authority is of the opinion that the measure is required to be modified in respect of imports from China imposed vide Customs Notification No. 47/2021 – Customs (ADD), dated 26th August 2021. Accordingly, definitive antidumping duty as per amount specified in Col. 7 of the table below is recommended to be imposed from the date of this notification till the remaining period of the duty that is upto 25.08.2026 which is imposed vide

Customs notification no. 47/2021-Customs dated 26.08.2021 in the event of acceptance of these recommendations by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from China PR.

117. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

SN	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	32064990, 32061900, 32041759, 32041739, 32041720, 32041790, 32071040	Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade	China PR	Any country including China PR	Fujian Kuncai Material Technology Company Limited	299	Per MT	US\$
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Coloray Technology Development Co., Ltd.	2913	Per MT	US\$
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Henan Lingbao New Materials Technology Co., Ltd	2353	Per MT	US\$
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than serial no 1 to 3	3144	Per MT	US\$
5	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any Producer	3144	Per MT	US\$

O. Further Procedure

118. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority